@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नई दिल्ली, शुक्रवार, 15 मई 2026, वर्ष-1, अंक-181, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

सिर्फ रोमांटिक फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहतीं लिंडसे लोहान... पेज 8

केजरीवाल, सिसोदिया समेत 6 नेताओं पर होगी अवमानना की कार्यवाही

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। कोर्ट ने माना कि आबकारी नीति मामले से जुड़ी कार्यवाही के संबंध में न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया गया था।

जस्टिस स्वरना कांता शर्मा ने एक विस्तृत आदेश जारी करते हुए कहा कि जब उन्होंने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया, तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और सार्वजनिक बयान दिए गए, जो निष्पक्ष आलोचना और आपराधिक अवमानना के बीच की सीमा को पार कर गए। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अवमानना करने वालों ने न केवल असहमति व्यक्त की, बल्कि इस मौजूदा जज के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पूरी न्यायपालिका के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और आप नेता सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि हालांकि जजों को निष्पक्ष आलोचना और असहमति स्वीकार करने के

लिए प्रशिक्षित किया जाता है। चुप रहना न्यायिक संयम नहीं है, जब न्यायपालिका को बदनाम करने का एक सोची-समझी कोशिश की जाती है। जज ने कहा कि यह अदालत सहानुभूति या आलोचना से छूट की मांग नहीं कर रही है। लेकिन अगर सुनियोजित अभियानों के माध्यम से न्यायपालिका की संस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जाती हैं, तो अदालत के पास कार्रवाई करने की शक्ति और कर्तव्य है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेशों की आलोचना करना तो जायज है, लेकिन निष्पक्ष आलोचना और 'कोर्ट की अवमानना' के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर होती है।

कोर्ट ने कहा कि कोई भी आम नागरिक किसी भी जज या आदेश की आलोचना कर सकता है। इसे अवमानना नहीं माना जाता। लेकिन, निष्पक्ष आलोचना और किसी जज को पक्षपाती दिखाने के लिए एक मुहिम चलाने में फर्क होता है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने खुद को केस से अलग रखने की अर्जी खारिज होने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बजाय, इस मामले को सोशल मीडिया पर ले जाने का रास्ता चुना। उन्होंने चिट्ठियां और वीडियो जारी करके जस्टिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। जज ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इसके बजाय, उन्होंने सार्वजनिक रूप से चिट्ठियां और वीडियो फैलाए, जिनमें राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया गया था और यह संकेत दिया गया था कि इस अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती।

दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार, यह रवैया न्यायपालिका के प्रति जनता में अविश्वास पैदा करने की एक कोशिश थी और अगर इसे न रोका गया, तो इससे अराजकता फैल जाएगी। जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को भी इस विवाद में घसीटा गया। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव अभियान का हिस्सा था, जिसका मकसद उन पर दबाव डालकर उन्हें इस केस से खुद को अलग करने के लिए मजबूर करना था।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। चुप रहना हार मान लेने जैसा होता। उन्होंने साफ किया कि अवमानना की यह कार्यवाही किसी निजी गुस्से या शिकायत की वजह से नहीं, बल्कि न्यायपालिका जैसी संस्था की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। जज आते-जाते रहेंगे, लेकिन न्याय की संस्था हमेशा बनी रहेगी।

सार समाचार

ज्ञानवापी मामले में वुजूखाना एएसआई सर्वेक्षण याचिका पर सुनवाई टली

प्रयागराज, एजेंसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को टाल दी। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई, 2026 की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल, वाराणसी की एक अदालत में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सुनवाई टाल दी।

केरल में विधायक दल के नेता चुने गए सतीशन

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन राज्य के नये मुख्यमंत्री होंगे। वह सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सतीशन ने आज यहां लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस की केरल प्रदेश प्रभारी दीपा दास मुंशी तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ भी थे। केरल में दस वर्षों के बाद श्री सतीशन के नेतृत्व में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की सरकार बनेगी। निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

स्लीपर बस में महिला से सामूहिक बलात्कार, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में काम से घर लौट रही 30 वर्षीय शादीशुदा महिला को एक निजी स्लीपर बस के अंदर कथित तौर पर घसीटकर ले जाया गया और चालक व परिचालक ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस बाबत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। साल 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड की याद दिलाने वाली यह घटना 11 मई को हुई।

पुलिस सूत्रों ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि महिला मंगोलपुरी इलाके की एक फैक्टरी में काम करने के बाद घर लौट रही थी और सरस्वती विहार के बी-ब्लॉक बस स्टैंड के पास पहुंचते ही उसको आरोपियों में से एक को बस के दरवाजे के पास खड़ा देखा और उससे समय पूछा। इसके बाद आरोपी ने उसे कथित तौर पर बस के अंदर खींच लिया और नांगलोई की

ओर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। विवाहित और तीन बच्चों की मां के बयान के अनुसार, दोनों पुरुषों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस समय महिला पर हमला हुआ, उस समय बस नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी। बस को जब्त कर लिया गया है। बाहरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विक्रम सिंह ने एक वीडियो बयान में कहा, 'रानी बाग थाने में हमें एक महिला के साथ कथित बलात्कार की सूचना मिली। तुरंत उसका बयान दर्ज किया गया और बिना देरी किए प्राथमिकी दर्ज की गई।

नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक: पांच आरोपी सात दिन के लिए सीबीआई हिरासत में

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की सात दिन की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने इसी के साथ टिप्पणी की कि इन आरोपों से संकेत मिलता है कि परीक्षा के गोपनीय प्रश्न पत्रों को लीक करने और आर्थिक लाभ के लिए प्रसारित करने में एक ''संगठित गिरोह'' की भूमिका थी। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने संघीय एजेंसी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें यश यादव, मांगीलाल खटीक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और शुभम मधुकर खैरनार को सात दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा, इस मामले में एक बड़ी साजिश का पहलू मौजूद है।

टुकड़ों में नहीं हो सकती शांति स्थापित: जयशंकर

भारत ने पश्चिम एशिया संकट और एकतरफा प्रतिबंधों पर गंभीर चिंता जताई

नई दिल्ली,एजेंसी।

भारत ने पश्चिम एशिया के संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल आपूर्ति तथा समुद्री स्थिरता पर इसके प्रभाव के संबंध में गंभीर चिंता जताते हुए ब्रिक्स देशों से भू-राजनीतिक उथल-पुथल से बेहतर ढंग से निपटने के लिए व्यावहारिक तरीके खोजने का आग्रह किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह टिप्पणी यहां आयोजित ब्रिक्स के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में की। जयशंकर ने किसी देश विशेष का नाम लिए बिना कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित होने चाहिए और किसी संघर्ष के समाधान के लिए 'संवाद और कूटनीति' ही सतत मार्ग प्रदान करते हैं।

जयशंकर ने कहा कि भारत तनाव कम करने की कोशिशों में अच्छा योगदान देने और स्थिरता बहाल करने की कोशिशों को समर्थन देने के लिए तैयार है। साथ ही, उन्होंने कहा कि शांति टुकड़ों में नहीं हो सकती और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना, आम लोगों की रक्षा करना और सार्वजनिक ढांचे को निशाना बनाने से बचना ज़रूरी है।उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि नए सदस्य देशों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर ब्रिक्स की सहमति आधारित व्यवस्था को पूरी तरह समझना और अपनाना जरूरी है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ईरान के बीच तीखे मतभेद सामने आए हैं।

यह पता चला है कि सम्मेलन के दो सत्र में से एक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार के बीच तीखी बहस हुई। शांति कायम करने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाल के हफ्तों में यूएई में ऊर्जा अवसंरचना पर ईरान के हमलों को लेकर ईरान और यूएई के बीच तीखी बयानबाजी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिक्स पश्चिम एशिया संकट पर एक सर्वसम्मत बयान जारी करने में विफल रहा है।

ब्रिक्स में शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। 2024 में इसका विस्तार कर इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। वर्ष 2025 में इंडोनेशिया भी इस समूह का सदस्य बना। जयशंकर ने कहा, ब्रिक्स की सुचारु प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि बाद में जुड़े सदस्य विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर ब्रिक्स की सहमति को पूरी तरह समझें और उसका समर्थन करें। विदेश मंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर से सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करने की भी ज़ोरदार वकालत की और गाजा में लड़ाई के 'गंभीर मानवीय असर' पर चिंता जताई। भारत की मेजबानी में हुई यह बैठक इसलिए और भी जरूरी हो गई है क्योंकि यह प्रभावशाली समूह पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक नतीजों, खासकर ऊर्जा आपूर्ति में भारी रुकावटों और व्यापार तथा शुल्क पर अमेरिका की नीति से जूझ रहा है।

अराघची और लावरोव के अलावा, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो और दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्री रोनाल्ड लामोला भी बैठक में उपस्थित वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे। जयशंकर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। लगातार तनाव, समुद्री यातायात के लिए जोखिम और ऊर्जा ढांचे में रुकावटें स्थिति की नाजुकता को दिखाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि होर्मुज और लाल सागर समेत अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवागमन वैश्विक आर्थिक भलाई के लिए अहम हो गया है। उन्होंने कहा, पूरे क्षेत्र में भी गंभीर चिंताएं हैं। गाजा संघर्ष के मानवीय परिणाम गंभीर हैं।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने की मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली,एजेंसी। ब्रिक्स की बैठक में भाग लेने यहां आये सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार को बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सग्रेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियेरा सहित सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। लावरोव ने श्री मोदी से अलग से भी मुलाकात की और पिछले वर्ष दिसंबर में हुई 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक के बाद द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग होने के अपने पहले के दृष्टिकोण को दोहराया। प्रधानमंत्री ने श्री लावरोव से राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को उनकी शुभकामनाएं देने का भी अनुरोध किया।

चुनाव बाद हिंसा के दौरान पुलिस निष्क्रिय रही, बंगाल बुलडोजर राज्य नहीं : ममता

कोलकाता, एजेंसी।

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा कि पश्चिम बंगाल में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान पुलिस निष्क्रिय रही। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अवैध ढांचों के खिलाफ जारी विध्वंस अभियान के बीच कहा कि यह (बंगाल) बुलडोजर राज्य नहीं है।

ममता विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित हिंसा और पार्टी दफ्तरों पर हमलों से जुड़े मामले में दलीलें देने के लिए बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में पेश हुईं। उन्होंने राज्य के लोगों को हमलावरों से बचाने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

एलएलबी डिग्री धारी ममता हाल के समय में किसी मामले में

वकील के तौर पर दलीलें पेश करने के लिए अदालत में दूसरी बार पेश हुईं। वहीं, बंगाल चुनाव में तृणमूल की हार के बाद यह बतौर वकील अदालत में उनकी पहली उपस्थिति थी। इससे पहले उन्होंने राज्य में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलीलें दी थीं। ममता वकील का गाउन पहनकर उच्च न्यायालय पहुंचीं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी भी उनके साथ थे। चंद्रिमा और कल्याण बनर्जी के पास भी कानून की डिग्री है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कल्याण बनर्जी के बेटे और उत्तरपाड़ा विधानसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार शीर्षन्या बंद्योपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेना की खंडपीठ के समक्ष दलीलें पेश कीं। ममता ने कहा कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राज्य में कम से कम 10 लोगों की हत्या कर दी गई, तृणमूल कांग्रेस के लगभग 150-160 कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और हिंसा की लगभग 2,000 घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा, 10 मृतकों में से छह हिंदू हैं। कृपया पुलिस से उचित कार्रवाई करने के लिए कहें। वे पुलिस को प्राथमिकी दर्ज नहीं करने दे रहे हैं।

तीसरे चरण की शुरुआत के साथ एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी, हालांकि इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं होंगे

सोलह राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में होगा एसआईआर

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत करने की घोषणा की। आयोग ने कहा कि यह एक बड़ा देशव्यापी अभियान होगा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों की सटीकता और पारदर्शिता को मजबूत करना है। आयोग के अनुसार, एसआईआर के तीसरे चरण का कार्यक्रम वर्तमान में जनगणना के तहत चल रहे मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया में लगी साझा फील्ड मशीनरी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।

तीसरे चरण की शुरुआत के साथ एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी, हालांकि इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं होंगे। आयोग ने कहा कि इन तीन क्षेत्रों का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। यह निर्णय जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊंचाई वाले तथा बर्फ से ढके क्षेत्रों में मौसम संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे इस संशोधन अभियान के तहत 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) गणना चरण में लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। इन बीएलओ की मदद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नामित लगभग 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) करेंगे।

ईसीआई ने एसआईआर को एक 'सहभागी और पारदर्शी प्रक्रिया' बताया है, जिसमें कई स्तरों पर मतदाता, राजनीतिक दल और चुनाव अधिकारी शामिल होते हैं। राजनीतिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे संशोधन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, समावेशिता और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए हर मतदान केंद्र पर बूथ स्तर के एजेंट नियुक्त करें।

ज्ञानेश कुमार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत के अवसर पर कहा, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे एसआईआर के तीसरे चरण में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और अपने गणना फॉर्म भरें। एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाता ही शामिल हों और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम न रहे।

आयोग ने आगे कहा कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए एसआईआर अभ्यास के पहले दो चरणों में संबंधित एसआईआर आदेश जारी होने की तारीख तक लगभग 59 करोड़ मतदाता शामिल थे।

इसमें कहा गया है कि इन चरणों के दौरान प्रक्रिया के अलग-अलग स्तरों पर 6.3 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी और 9.2 लाख बूथ लेवल एजेंट को तैनात किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस गहन संशोधन अभियान का उद्देश्य डुप्लीकेट, स्थानांतरित, मृत या अयोग्य नामों की पहचान करके मतदाता सूची को सही और त्रुटि-मुक्त बनाना है। साथ ही सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना भी इसका लक्ष्य है।

संघर्ष के चारों दिन हमने अपना दबदबा बनाए रखा: सीडीएस चौहान

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बृहस्पतिवार को कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के पास स्थिति की अच्छी जानकारी और युद्धक्षेत्र में बेहतर पारदर्शिता थी, तथा उन्होंने संघर्ष के चारों दिन दबदबा बनाए रखा।

यहां मानेकशॉ सेंटर में आयोजित 'कलम और कवच' रक्षा सम्मेलन में एक संवाद सत्र के दौरान उनकी यह टिप्पणी, देश और सशस्त्र बलों द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ मनाए जाने के कुछ दिन बाद आई। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, चारों दिन हमने स्थिति की व्यापक जानकारी के कारण तनाव के स्तर पर हर तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। हमें पता था कि

हमने किसको निशाना बनाया है, क्या हो रहा है। सीडीएस ने कहा कि भारतीय सेना को न केवल अपनी तरफ बल्कि सीमा पार भी स्थिति की बेहतर जानकारी थी, और ''हम तनाव के हर स्तर पर दबदबा बनाए रखने में सक्षम थे।

यह पूछे जाने पर कि ड्रोन और उन्नत हथियारों के प्रभुत्व वाले युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए वह भविष्य के युद्धक्षेत्र की कल्पना कैसे करते हैं, उन्होंने लंबे समय तक जारी रहने वाले संघर्षों में उलझने को लेकर आगाह किया।

मणिपुर में भड़की हिंसा में चार की मौत

इम्फाल,एजेंसी। मणिपुर में दो समूहों के बीच फिर से भड़की हिंसा में अज्ञात व्यक्तियों ने अलग-अलग समुदायों के चार लोगों की हत्या कर दी है और 38 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया है। राज्य के गृह मंत्री के. गोविंदस ने कहा है कि अगवा किए गए लोगों को सुरक्षित छुड़ाने के प्रयास जारी हैं। बुधवार को जैसे ही हत्याओं की खबर फैली, दोनों समुदायों के लोगों ने अलग-अलग इलाकों में दूसरे संघर्षरत समुदायों के लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया।

गृह मंत्री ने अगवा किए गए लोगों का विवरण साझा नहीं किया। उन्होंने आज जेएनआईएमएस अस्पताल का दौरा किया, जहां उनके साथ विधायक अवांगबो न्यूमई, काशिम वाशुम, जमेनलुंग पामेई और दीपू गंगमेई भी मौजूद थे।

फरीदाबाद नगर निगम के निर्माण कार्यों की जांच की तैयारी

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की नाराजगी के बाद नगर निगम समेत विभिन्न एजेंसियों के निर्माण कार्यों की विजिलेंस जांच कराने की तैयारी की जा रही है।

फरीदाबाद,एजेंसी।

शहर में करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई सड़कों के कुछ ही महीनों में टूटने और बदहाल होने के मामलों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की नाराजगी के बाद नगर निगम समेत विभिन्न एजेंसियों के निर्माण कार्यों की विजिलेंस जांच कराने की तैयारी की जा रही है। नगर निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे निगम में हड़कंप का माहौल है, अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई है।

दरअसल मंगलवार को हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। उनके निशाने पर नगर निगम, एफएमडीए, मार्केटिंग बोर्ड

और जिला परिषद के अधिकारी रहे। बैठक में निर्माण कार्यों की जांच मुख्य विजिलेंस अधिकारी से कराने की बात भी कही गई।

सबसे ज्यादा चर्चा नवादा से पृथला विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया की शिकायत पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। इसके अलावा सेक्टर-दो में करीब सालभर पहले बनी तारकोल की सड़कें भी जगह-जगह से टूट चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद केवल खानापूरी की गई।

खेड़ी पुल से मंझावली तक बनी सड़क और अनखीर चौक से सूरजकुंड गोल चक्कर तक एफएमडीए की चार लेन सड़क की हालत भी कई जगह खराब हो चुकी है। वहीं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली वाईसीएम रोड, कोर्ट रोड और सेक्टर-15-16 डिवाइडिंग रोड भी निर्माण के कुछ महीने बाद ही टूटने लगी थीं। निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जो सड़कें निर्माण के कुछ समय बाद ही खराब हुई हैं। उनकी जांच कराई जाएगी और संबंधित कार्यकारी अभियंताओं की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

चौड़ी सड़कों की सफाई मशीनों से कराने की तैयारी

फरीदाबाद, एजेंसी। शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम ने नई कार्ययोजना तैयार की है। योजना के तहत पहली बार सड़कों की चौड़ाई और क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार चार अलग-अलग स्तर पर सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और अगले महीने से योजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है। व्यवस्था पर करीब 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पिछले करीब 15 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित रही। कई इलाकों में कचरे के ढेर लगने और नियमित सफाई नहीं होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। मंगलवार को नगर निगम की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा स्वयं फील्ड में उतरे और कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से कचरा उठवाया गया।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार नई योजना के तहत 10 मीटर से अधिक चौड़ी मुख्य सड़कों और हाईवे से जुड़े मार्गों की सफाई आधुनिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों से कराई जाएगी। ये मशीनें धूल और कचरा हटाने के साथ पानी का छिड़काव भी करेंगी, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। वहीं 5 से 10 मीटर चौड़ी सड़कों पर सफाई कर्मचारियों की अलग टीमें तैनात की जाएंगी। उन्हें तय रूट और समय के अनुसार सफाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। कॉलोनियों और संकरी गलियों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, झाड़ू लगाने और कूड़ा उठाने का काम अलग एजेंसियों और निगम कर्मचारियों के माध्यम से कराया जाएगा। बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में रात के समय विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत शहर को चार जोन में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन में अलग निगरानी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सफाई कार्य में लगे वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सफाई कार्य की फोटो और लोकेशन आधारित रिपोर्ट भी तैयार होगी, जिससे जवाबदेही तय की जा सकेगी। नगर निगम का दावा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद मुख्य सड़कों पर धूल कम होगी, कचरा समय पर उठेगा और लोगों को बेहतर स्वच्छ वातावरण मिलेगा।

बाढ़ आपदा प्रबंधन की परखी तैयारी, दस मिनट में राहत कार्य शुरू

नूंह,एजेंसी।

मानसून से पहले संभावित बाढ़ और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए गुरुवार को आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान जिला प्रशासन की टीमों ने राहत कार्य किया। कई जगह टीम दस मिनट में राहत कार्य करने में जुट गई थी। मॉक ड्रिल में राहत एवं बचाव एजेंसियों ने त्वरित प्रतिक्रिया, बेहतर तालमेल और मुस्तैदी का प्रदर्शन किया। सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर से रवाना हुईं टीमें में ओल्ड अंडरपास पहुंचीं और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए गए।

इस दौरान टीम की तत्परता को देखकर आसपास के लोग हैरत में रह गए। उन्हें किसी बड़ी आपदा का अहसास हुए। लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि यह एक अभ्यास था। सुबह ठीक नौ बजे साइरन बजने

के साथ मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई। सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर से एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सेवा, सिविल डिफेंस, रेडक्रॉस, पुलिस, नेवी, एनसीसी कैडेट्स और अन्य विभागों की टीमें अपने निर्धारित वाहनों के साथ रवाना हुईं। प्रशासन की ओर से तय समय के अनुसार सभी राहत टीमें करीब 10 मिनट में ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास पहुंच गईं और मात्र 10 मिनट के भीतर राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया।

मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ और जलभराव की वास्तविक स्थिति जैसा दृश्य तैयार किया गया। इसमें कई लोगों के अंडरपास में फंसने, कुछ लोगों के घायल होने और वाहनों के पानी में फंसने की स्थिति दिखाई गई। इसके बाद रेस्क्यू टीमों ने नावों, रस्सियों और आधुनिक उपकरणों की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की।

गाजियाबाद में सीवर से बनेगी सीएनजी, लगेगा यूपी का पहला बायो-सीएनजी प्लांट

गाजियाबाद, एजेंसी।

गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में सीवर के पानी से बायो सीएनजी बनाने का यूपी का पहला प्लांट एक साल में तैयार होगा। नगर निगम और कंपनी के बीच हुए इस समझौते के तहत रोजाना 1700 किलो गैस बनेगी जिससे पलूशन कम होगा। गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा में सीवर से बायो सीएनजी बनाने वाला यूपी का अनूठा प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और संबंधित कंपनी के बीच समझौता हो चुका है।

यह प्लांट एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पीपीपी मॉडल पर आधारित इस परियोजना से प्रतिदिन 1700 किलो सीएनजी का उत्पादन होगा जिसका उपयोग लगभग 3050 घरों और 350 वाहनों में किया जा सकेगा। यह पहल मीथेन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण संरक्षण में

मदद करेगी। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में अन्य STP केंद्रों पर भी ऐसे ही आधुनिक प्लांट लगाए जाएंगे।

गाजियाबाद नगर निगम के अनुसार, डूंडाहेडा स्थित एसटीपी पर सीवर से बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए बुधवार को नगर निगम और प्लांट लगाने वाली कंपनी के बीच करार हो गया। प्लांट एक साल में तैयार हो जाएगा। निगम का कहना है कि इस बायो सीएनजी प्लांट शुरू होने से पर्यावरण में भी सुधार होगा। महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की मौजूदगी में बुधवार को निगम सभागार में बायो सीएनजी प्लांट लगाने वाली कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए। नगर आयुक्त ने बताया कि यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बीओटी पर विकसित की जाएगी।

प्रस्तावित परियोजना में अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया के दौरान बायोगैस का उपयोग कर उसे उच्च गुणवत्ता वालीबायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। परिवहन एवं औद्योगिक क्षेत्र में गैस का उपयोग किया जा सकेगा। अप शिष्ट जल से प्राप्त बायोगैस को स्वच्छ ऊर्जा में बदलने से परियोजना मीथेन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाएगी।

इससे पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में योगदान देगी। प्लांट पर एक दिन में 70 एमएलडी सीवर के पानी से करीब 1700 किलो सीएनजी बनेगी। इस गैस का 3050 घरों और 350 वाहनों में इस्तेमाल हो सकेगा। नगर आयुक्त का दावा है कि उत्तर प्रदेश का यह पहला प्लांट बनाया जा रहा है।

मिनी ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत

नोएडा,एजेंसी।

सलारपुर गांव स्थित भंगेल एलिवेटेड रोड पर बुधवार शाम मिनी ट्रक के चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल स्कूटी सवार को उपचार के लिए नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कुलेसरा गांव निवासी 36 वर्षीय केशव गुप्ता स्कूटी पर सवार होकर कुलेसरा से नोएडा जा रहे थे। भंगेल एलिवेटेड रोड पर सलारपुर गांव के पास एक मिनी ट्रक के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पार्क में सिंथेटिक ट्रैक बनाने का कार्य शुरू

सोहना,एजेंसी।

शहर के राजीव गांधी पार्क में सिंथेटिक ट्रैक बनाने का कार्य शुरू हो गया है। पार्क में सिंथेटिक ट्रैक बनाने पर नगर परिषद 90 लाख रुपये खर्च करेगी। पार्क में घूमने के लिए आने वाले लोगों को बरसात के मौसम में चलना आसान होगा। शहर के वार्ड 20 में करीब चार एकड़ जमीन पर बना राजीव गांधी पार्क में घूमने के लिए 731 मीटर लंबा ट्रैक बना है। जिस पर निर्माण के दौरान मिट्टी की टेल लगाई गई थी। लेकिन नगर परिषद ने यहां घूमने वाले नागरिकों को पैदल चलने में सुविधा देने की योजना बनाई है।

परिषद की तरफ से ट्रैक पर चलने में लोगों की सुविधा मिले और किसी प्रकार से गिरने के दौरान चोट न लगे। इसके लिए परिषद ने पार्क के पूरे ट्रैक को सिंथेटिक बनाने की कवायद शुरु कर दी है। उक्त टैंक का कार्य बरसाती मौसम के शुरु होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

गश्त बढ़ाने के लिए 25 पीआरवी सड़क पर उतारे

नोएडा,एजेंसी।

गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गुरुवार को गश्त बढ़ाने और पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को मजबूत करने के लिए 25 नए दोपहिया पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) वाहनों को डायल-112 बेड़े में शामिल किया। सेक्टर-108 स्थित कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अलग-अलग थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इन नए पीआरवी वाहनों की तैनाती का मुख्य उद्देश्य शहर में पुलिस की सतर्कता बढ़ाना, ट्रैफिक और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तेजी से पहुंच सुनिश्चित करना और इमरजेंसी कॉल पर तुरंत कार्रवाई करना है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन वाहनों के शामिल होने से डायल-112 की प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत होगी।

खासकर संकरी सड़कों, बाजारों और हाई ट्रैफिक वाले इलाकों में पुलिस पहले से ज्यादा तेजी से मौके

पर पहुंच सकेगी। यह पीआरवी तीनों जोन में चलेंगी। इनमें नोएडा जोन में 10, सेंट्रल नोएडा जोन में 10 और ग्रेटर नोएडा जोन को पांच अतिरिक्त पीआरवी मिली हैं।

कमिश्नरेट लगातार आधुनिक तकनीक, उन्नत संसाधनों और नए वाहनों को शामिल कर पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत कर रहा है। इसका उद्देश्य आम लोगों को बेहतर सुरक्षा और तेज पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। इस मौके पर अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. राजीव नारायण मिश्र, पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभारी डीसीपी ट्रैफिक एवं डायल-112 अभय कुमार मिश्र और एसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल शकील अहमद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सीनियर-डिप्टी मेयर का चुनाव अगले हफ्ते संभव

गुरुग्राम,एजेंसी।

नगर निगम गुरुग्राम में पिछले 13 महीने से खाली पड़े सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर जल्द ही काबिज होने वाले चेहरों से पर्दा उठने वाला है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो इसी सप्ताह चुनाव की तारीख का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा और अगले सप्ताह चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। हाल ही में हुई निगम सदन की बैठक में निगम आयुक्त ने भी स्पष्ट किया था कि 24 मई से पहले इन दोनों पदों के लिए चुनाव करवा लिए जाएंगे।

इस बार चुनाव की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प होने वाली है। प्रशासन की योजना चुनाव को बिना किसी विवाद के सर्वसम्मति से निपटाने की है। तय रणनीति के अनुसार, चुनाव में मतदान की नौबत आने से पहले सभी पार्षदों की सहमति ली जाएगी। इसके बाद सीधे तौर पर बंद पर्ची खोलकर नाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि इस पर्ची सिस्टम पर किसी पार्षद या गुट ने विरोध दर्ज कराया, तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पार्षदों के मतदान के जरिए ही दोनों दावेदारों का अंतिम चयन किया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे पहले 30 अप्रैल को इन दोनों पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित थे। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और बड़ी संख्या में पार्षद मतदान के लिए हिपा कार्यालय पहुंच भी चुके थे। लेकिन, चुनाव वाले दिन ही अचानक मेयर राजरानी मल्होत्रा की तबीयत बिगड़ गई। मेयर की अनुपस्थिति के कारण मतदान प्रक्रिया को अंतिम समय में स्थगित करना पड़ा था। इसके अलावा, चुनाव में लगातार हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने आठ सप्ताह के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।

नगर निगम का सदन पिछले 13 महीनों से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के बिना ही संचालित हो रहा है। ऐसे में चुनाव की सुगबुगाहट से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निगम सदन में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है, जिसके चलते दोनों पदों का भाजपा के खाते में जाना लगभग तय है। हालांकि, पार्टी के भीतर दावेदारों की लंबी कतार है और अलग-अलग गुट अपने-अपने समर्थित चेहरों को इन पदों पर बैठाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी जोड़-तोड़ और तेज होने की पूरी संभावना है।

फ्लाईओवर से कारोबार को लाभ मिलेगा

गुरुग्राम,एजेंसी।

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (एनएच-48) पर मानेसर क्षेत्र में लंबे समय से लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से परेशान उद्यमियों और स्थानीय लोगों के लिए अब बड़ी राहत की खबर है। मानेसर फ्लाईओवर निर्माण कार्य की शुरुआत को उद्योग जगत ने सकारात्मक कदम बताया है। कुछ समय पहले सीआईआई हरियाणा काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य व कैपारो मारुति के सीईओ विनोद बापना ने इस फ्लाईओवर के मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाया था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। उसके बाद यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष पहुंचा।

केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार के सहयोग से बिना किसी देरी के उद्योग जगत की समस्याओं को समझते हुए फ्लाईओवर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। विनोद बापना ने कहा कि यह फ्लाईओवर केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र के विकास का मजबूत आधार साबित होगा। इससे गुरुग्राम, मानेसर, बावल, धारूहेड़ा तथा गुरुग्राम के आसपास स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। कच्चा माल और तैयार उत्पादों की आवाजाही में आसानी होगी।

सप्लाई चेन मजबूत होगी और यातायात सुगम होने से उद्योगों की कार्यक्षमता में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि यातायात की सुविधाएं बेहतर होती हैं, वहां विकास की गति भी तेज होती है। बेहतर सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था से निवेश को बढ़ावा मिलता है। लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम के कारण उद्योगों को समय, ईंधन और उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन इस परियोजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य मंत्री ने 2.86 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाएं की जनता को समर्पित

गुरुग्राम,एजेंसी।

हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने गुरुवार को गुरुग्राम जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में करीब 2.86 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित कीं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में पटौदी की विधायक बिमला चौधरी भी मौजूद रही।

स्वास्थ्य मंत्री ने उपमण्डल नागरिक अस्पताल हेलीमण्डी में लगभग 50 लाख रुपये की लागत से स्थापित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) का उद्घाटन किया।

यह यूनिट पटौदी ब्लॉक के लिए डायग्नोस्टिक हब के रूप में कार्य

करेगी, जहां एचबी, ईएसआर, आरबीएस, डेंगू, मलेरिया, ब्लड ग्रुप सहित विभिन्न लैब जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने गांव चन्दू में लगभग 89.45 लाख रुपये की लागत से निर्मित आम उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, नूरगढ़ और महचाना गांवों में निर्मित नए उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का भी उद्घाटन किया।

नूरगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र भवन लगभग 81.89 लाख रुपये तथा महचाना उप स्वास्थ्य केंद्र भवन लगभग 64.83 लाख रुपये की लागत से तैयार किए गए हैं। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा का सर्वाधिक आबादी वाला जिला होने के कारण यहां स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और तेज शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। ताकि आमजन को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। नए अस्पताल भवनों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आरती सिंह राव ने कहा कि गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नई विकास परियोजनाएं भी पाइपलाइन में हैं।

उन्होंने बताया कि जिले के बाघनकी क्षेत्र में एक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की स्थापना की जाएगी, जबकि घामड़ोज गांव में नया सब हेल्थ सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में गुरुग्राम जिले के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को और मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है।

कॉल कर बुलाई युवती अगले दिन मृत मिली

नोएडा,एजेंसी।

चोटपुर कॉलोनी निवासी युवक ने बुधवार रात कॉल गर्ल को अपने कमरे पर बुलाया। गुरुवार सुबह युवती मृत मिली। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक चोटपुर कॉलोनी में एक युवक किराये के घर में रहता है। वह एक प्राइवेट फैक्टरी में नौकरी करता है। वह गुरुवार सुबह थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने बुधवार रात एक युवती को कॉल करके बुलाया था।

रात में दोनों ने शराब का सेवन किया और सो गए। वह गुरुवार सुबह फैक्टरी जाने के लिए उठा तो उसने युवती को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठी। उसके एक कान से खून बह रहा था। इस पर वह घबरा गया और थाने पहुंचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से साक्ष्य एकत्र किए।

वीडियोग्राफी कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूछताछ में युवक ने पुलिस को बताया कि वह युवती का नाम और पता नहीं जानता। इससे पहले वह दो-तीन बार उसे कमरे पर बुला चुका था।

पुलिस को भी युवती के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला। लोगों की हत्या की आशंका जताई आस-पास के लोगों ने आशंका जताई कि युवक ने युवती की हत्या की है। पुलिस का कहना है कि चूंकि युवती के कान से खून निकल रहा था, इसलिए घटना संदिग्ध लग रही है। फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवती के मोबाइल फोन के नंबरों के जरिये उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

RNI.No DLHIN/25/A2841

स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मे. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

अगले एक वर्ष तक मंत्री और अधिकारी नहीं करेंगे आधिकारिक विदेशी दौरे: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से की गई सात प्रमुख अपीलें केवल सुझाव नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान हैं।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण, संसाधनों की बचत, 'वोकल फॉर लोकल' और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के आह्वान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सरकार की ओर से व्यापक जनभागीदारी अभियान 'मेरा भारत, मेरा योगदान' की घोषणा की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईंधन संकट और बढ़ती आयात लागत का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है।

ऐसे समय में देशहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संसाधनों की बचत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से की गई सात प्रमुख अपीलें केवल सुझाव नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान हैं। इन्हीं अपीलों को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए दिल्ली सरकार 'मेरा भारत, मेरा योगदान' नाम से 90 दिवसीय व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर रही है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत और ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए हैं। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सप्ताह में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था लागू की जाएगी। निजी कंपनियों और संस्थानों को भी अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो हेल्प डेस्क व कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही सरकार बड़ी कंपनियों और संस्थानों से व्यक्तिगत स्तर पर संवाद कर सहयोग सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था उन आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जो सीधे जन-सुविधाओं और सार्वजनिक कार्यों से जुड़ी हैं। इनमें पब्लिक डीलिंग से संबंधित विभाग, फायर सर्विस, अस्पताल, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, बिजली एवं जल आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्तर पर वाहनों के उपयोग को न्यूनतम किया जाएगा। नए निर्णय के अनुसार अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। जिन वाहनों की पहले 200 लीटर पेट्रोल की सीमा थी, उसे घटाकर 160 लीटर तथा 250 लीटर की सीमा को घटाकर 200 लीटर किया गया है।

उन्होंने बताया कि हर सोमवार को 'मेट्रो मंडे' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जहां तक संभव होगा, मेट्रो एवं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि दिल्ली नगर निगम कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9 से शाम 5:30 बजे है। कार्यालयों के समय के इस अंतराल से ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने की अपील करते हुए कहा कि नागरिक अपनी सुविधा अनुसार एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि अगले छह महीने तक दिल्ली सरकार कोई नया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड वाहन नहीं खरीदेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ग्रेड-1 से ग्रेड-8 तक के कर्मचारियों और अधिकारियों को यदि वे अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो आदि पर खर्च करते हैं, तो सरकार की ओर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार माल वाहक कंपनियों से अपील की जाएगी कि वे अपने माल की ढुलाई ट्रकों के बजाय ट्रेन से करें।

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

कागज नहीं तो नागरिक नहीं?

नई दिल्ली। देश में पहली बार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जहां नागरिकता अदालत या संविधान से नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों और वोटर लिस्ट से तय होती दिखाई दे रही है। जिस मतदाता सूची का मकसद लोगों को लोकतंत्र से जोड़ना था, अब वही सूची लोगों को अधिकारों से बाहर करने का हथियार बनती जा रही है।

बिहार और पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकारों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बाद मतदाता सूची से हटे हैं, उन्हें राशन, पेंशन और दूसरी सरकारी योजनाओं से भी वंचित किया जा सकता है। यानी अब मामला केवल वोट डालने का नहीं रहा। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में गरीब आदमी को नागरिक साबित करने के लिए हर बार नया कागज देना पड़ेगा?

सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग खुद अदालत में कह चुका है कि मतदाता सूची में नाम न होना नागरिकता खत्म होने का प्रमाण नहीं है। फिर राज्य सरकारें किस कानून के तहत यह मान रही हैं कि सूची से नाम कटते ही व्यक्ति सरकारी योजनाओं का हकदार नहीं रह जाता? क्या अब प्रशासनिक त्रुटियां भी नागरिकता तय करेंगी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

पी चिदंबरम का यह सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर नागरिकता का आधार क्या है? संविधान या वोटर लिस्ट? अगर कल किसी तकनीकी गड़बड़ी से किसी व्यक्ति का नाम सूची से हट जाए, तो क्या वह अचानक "कम भारतीय" हो जाएगा?

असल समस्या यह है कि यह पूरी कवायद अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के खिलाफ सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगी। जिन लोगों के पास पुश्तैनी दस्तावेज नहीं हैं, जिनका जन्म अस्पतालों में नहीं हुआ, जिनकी जिंदगी पलायन, बाढ़, गरीबी और अशिक्षा में बीती l वह आखिर कौन से कागज दिखाएंगे? जिनकी दुनिया राशन कार्ड, आधार और मनरेगा तक सीमित है, अब उन्हीं से कहा जा रहा है कि पहले खुद को साबित करो।

यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि हजारों करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वालों की नागरिकता पर कभी सवाल नहीं उठते, लेकिन गांव का गरीब मजदूर शक के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। सत्ता के लिए सबसे आसान निशाना हमेशा वही लोग होते हैं जिनकी आवाज कमजोर होती है।

लोककल्याणकारी राज्य का मतलब यह नहीं होता कि सरकार केवल "योग्य" लोगों की मदद करे। संविधान ने राज्य को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह कमजोर, गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को सुरक्षा दे। लेकिन अब व्यवस्था उलटी दिशा में चलती दिख रही है। पहले नागरिक को संदिग्ध बनाओ, फिर उसके अधिकार सीमित करो, और आखिर में उसे योजनाओं से बाहर कर दो।

बिहार में लाखों और बंगाल में करोड़ के करीब नाम हटाए जाने की खबरें केवल आंकड़े नहीं हैं। यह आने वाले समय का संकेत हैं। आज राशन रोका जाएगा, कल पेंशन और छात्रवृत्ति, फिर इलाज और रोजगार पर सवाल उठेंगे। यानी नागरिकता धीरे-धीरे अधिकार नहीं, सरकारी मंजूरी का विषय बनती जाएगी।

सबसे बड़ा खतरा यही है कि लोकतंत्र में नागरिक और राज्य के बीच भरोसा टूटने लगे। अगर आम आदमी को यह डर सताने लगे कि किसी दिन एक सरकारी सूची उसे अधिकारविहीन बना सकती है, तो फिर संविधान की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है।

भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतांत्रिक समावेशिता रही है, न कि कागजों के जरिए लोगों की छंटनी। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि सरकार तय करे कौन "असल नागरिक" है और कौन नहीं। लोकतंत्र का मतलब यह है कि हर नागरिक को तब तक बराबरी का अधिकार मिले, जब तक कानून उसे दोषी साबित न कर दे।

आज जरूरत इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले पर स्पष्ट और कठोर रुख अपनाए। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट को नागरिकता की अनौपचारिक कसौटी बनने दिया गया, तो आने वाले समय में लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित रह जाएगा और नागरिकता सरकारी दफ्तरों की मेहरबानी बनकर रह जाएगी।

एमसीडी में भी वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग का सुझाव

नई दिल्ली,साहस समाचार।

एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर प्रशासनिक सुधारों के सुझाव दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से फ्यूल बचाने, प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की अपील की है। उन्होंने डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें करने पर जोर दिया ताकि गैरजरूरी यात्रा और सरकारी वाहनों के उपयोग को कम किया जा सके।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर व्यापक स्तर पर प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि निगम के अधिकारी और कर्मचारी अधिकतम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। साथ ही, जहां संभव हो वहां कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जाए।

गुरुवार को एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कार्यालय पहुंचने के लिए मेट्रो से यात्रा कर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से निजी और सरकारी वाहनों के उपयोग को कम किया जाना चाहिए। इससे ईंधन की बचत के साथ यातायात पर दबाव भी कम होगा। ईंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए यह समय सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का है। स्थायी समिति अध्यक्ष ने कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को भी अपनाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है, उनके लिए कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी जाए। उन्होंने आगे निर्देश दिए कि अधिकतर बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए आयोजित किया जाए। गौरतलब है कि एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा की ओर से दिए गए उक्त सुझाव ऐसे समय पर आए हैं जब दिल्ली सरकार ने फ्यूल बचाने और पलूशन कम करने के लिए 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अब हफ्ते में 2 दिन घर से काम करेंगे और ज्यादातर बैठकें ऑनलाइन की जाएंगी।

दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास अवैध पार्किंग पर हाईटेक निगरानी

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास अवैध और गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर अब हाईटेक कैमरों की नजर रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई नई तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था के तहत महज 10 दिनों में 100 से अधिक ई-चालान जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई 3 मई से शुरू हुई स्वचालित प्रवर्तन प्रणाली के तहत की गई, जिसमें अत्याधुनिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मई तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों को सत्यापन के बाद ई-चालान भेजे जा चुके हैं। वर्तमान में हवाई अड्डे के आसपास 14 हाई डेफिनिशन एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। इनमें सेंट्रल स्पाइन रोड, विभिन्न टर्मिनलों के पहुंच मार्ग, कार्गो क्षेत्र और रंगपुरी-सेंटौर जंक्शन के आसपास के हिस्से शामिल हैं। इनमें से 10 कैमरे विशेष रूप से अवैध पार्किंग की पहचान के लिए लगाए गए हैं। छह कैमरे सेंट्रल स्पाइन रोड और चार टर्मिनल-1 निकास मार्ग पर कार्यरत हैं।

अधिकारियों के अनुसार अभी यह कैमरा नेटवर्क हवाई अड्डे की कुल सड़क व्यवस्था के लगभग 15 प्रतिशत हिस्से को कवर कर रहा है। आने वाले समय में 50 से अधिक अतिरिक्त एएनपीआर कैमरों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे तीनों टर्मिनलों को जोड़ने वाले पूरे सड़क नेटवर्क की निगरानी और अधिक मजबूत हो सकेगी। डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा कि हवाई अड्डे के आसपास गलत पार्किंग लंबे समय से यातायात व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई थी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उन्नत तकनीक का उपयोग कर यातायात अनुशासन बढ़ाने और वाहनों की आवाजाही को सुचारु बनाने का प्रयास किया जा रहा है।वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त शोभित ने कहा कि अवैध पार्किंग से जाम, दुर्घटना का खतरा और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। नई एएनपीआर आधारित प्रणाली आदतन नियम तोड़ने वालों के लिए मजबूत निवारक साबित होगी क्योंकि अब उल्लंघनों की पहचान और कार्रवाई पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अधिक सटीकता के साथ हो रही है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत घोषित अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल (आईएससी) ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी पिछले सात सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस ने गुरुवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय हरप्रीत सिंह उर्फ मणि के रूप में हुई है, जो पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। 5 जनवरी 2018 को बठिंडा में दर्ज की गई एक एफआईआर में उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत 'घोषित अपराधी' बताया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पिछले सात सालों से लगातार अपनी छिपने की जगहें बदलकर और अपनी पहचान छिपाकर गिरफ्तारी से बच रहा था। जांच में यह भी पता चला कि वह एक और आपराधिक मामले में भी वांछित है, जो बठिंडा में ही दर्ज है। 5 जनवरी 2018 को बठिंडा कैंट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आरोपी हरप्रीत सिंह को तब गिरफ्तार किया, जब वह एक पॉलीथीन बैग में नशीली दवाएं ले जा रहा था। उसके कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित वस्तुओं में 'विंसरेक्स' सिरप की आठ बोतलें, 'ओनेरेक्स' सिरप की चार बोतलें और 'कैरिसोमा' टैबलेट की 15 स्ट्रिप्स शामिल थीं।संबंधित पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22/61/85 के तहत एफआईआर नंबर 03/2018 दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। बाद में, आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो गया और 23 सितंबर, 2020 को उसे 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया गया।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया मेट्रो में सफर

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने गुरुवार को नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन को व्यापक रूप से अपनाने का आग्रह किया और एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेट्रो के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर में स्वयं यात्रा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान संधू को सहयात्रियों से खुलकर बातचीत करने का अवसर मिला, जिनमें से कुछ ने उनके साथ सेल्फी लेने का अनुरोध भी किया। एक्स पर एक संदेश में संधू ने कहा कि मेट्रो के माध्यम से एक बार फिर शहर की धड़कन का अनुभव कर रहा हूं, जो कुशल, सुलभ और प्रतिदिन लाखों लोगों को जोड़ने वाली है।

उन्होंने कहा कि अपनी हाल की यात्राओं में, मैंने पाया है कि यह हमारे शहर में घूमने का सबसे कुशल तरीका है और साथ ही यह एक स्थायी पर्यावरण में योगदान भी देता है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जहां भी संभव हो, सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं। ये सामूहिक प्रयास, भले ही सरल हों, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वच्छ परिवहन साधनों के उपयोग के लिए संधू का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न 'चुनौतीपूर्ण अवधि' के लिए तैयार रहने की हालिया अपील के अनुरूप है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईंधन बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों के लिए दो दिन का अनिवार्य 'वर्क फ्रॉम होम' का आदेश भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार भी काफी कम कर दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए तैनात विशिष्ट बल, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को अपने काफिले का आकार न्यूनतम रखने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की असम की हालिया यात्राओं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने के दौरान काफिलों की संख्या सामान्य से कम कर दी गई थी।

एसपीजी ने वाहनों की संख्या कम करके निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया है; हालांकि, प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखी गई है। यह कदम विपक्ष की आलोचना के बाद उठाया गया है, जिसने मोदी सरकार पर नागरिकों पर कठोर उपाय थोपने और खुद को वैश्विक तेल संकट से अछूता रखने का आरोप लगाया था।

कार ने युवती को मारी टक्कर, पैर की हड्डी टूटी

नई दिल्ली,साहस समाचार। रका नार्थ इलाके में सड़क पार करने के दौरान एक कार ने युवती को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवती का एक पैर की हड्डी टूट गई। पीड़िता की पहचान 22 साल की पिंकी के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देकर कार समेत भाग रहे चालक को लोगों ने दबोच लिया। पुलिस के सामने चालक ने इलाज के लिए पैसे देने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में मुकर गया।

उसके बाद 13 मई को पीड़िता ने चालक के खिलाफ थाने में शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। मूलतः हमीरपुर यूपी की रहने वाली 22 साल का पिंकी परिवार के साथ पालम कॉलोनी में रहती है।

सफदरजंग में अब एक विभाग से दूसरे विभाग जाना हुआ आसान

नई दिल्ली,साहस समाचार।

अस्पताल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ई-एंबुलेंस का उद्घाटन अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता शर्मा ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चारु बांबा और डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई) इंडिया के अध्यक्ष डॉ. रजत जैन की उपस्थिति में किया गया। सफदरजंग में अब एक विभाग से दूसरे विभाग जाना हुआ आसान, ई-एंबुलेंस शुरू राजधानी के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेजऔर सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है।

अस्पताल को अपनी पहली अत्याधुनिक ई-एंबुलेंस मिली है। डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई) इंडिया ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के तहत वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल को ये ई-एंबुलेंस दान की है। ई-एंबुलेंस अस्पताल परिसर के भीतर मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में इस्तेमाल होगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन मोबिलिटी, टिकाऊ स्वास्थ्य देखभाल और हेल्थ सेक्टर में बुनियादी ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है।

अस्पताल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ई-एंबुलेंस का उद्घाटन अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता शर्मा ने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चारु बांबा और डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई) इंडिया के अध्यक्ष डॉ. रजत जैन की मौजूदगी में किया गया। बयान के मुताबिक, यह ई-एंबुलेंस अस्पताल परिसर के भीतर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण मुक्त आवाजाही और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है, साथ ही पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता को कम करना है।

डॉ. कविता शर्मा ने कहा, 'वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, और मरीजों की सुविधा बढ़ाने वाले कदम हमेशा मूल्यवान होते हैं। सीएसआर पहल के तहत ई-एंबुलेंस दान देने के लिए डीएफवाई इंडिया की सराहना करते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल है और अस्पताल परिसर के भीतर मरीजों की आवाजाही में बड़ी ही कारगर साबित होगी। वहीं डॉ. रजत जैन ने कहा कि डॉक्टर्स फॉर यू इंडिया अपनी सीएसआर पहल के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करने के लिए पूरी तरह समर्पित है।

यह पहल अस्पतालों और बड़ी कंपनियों के बीच बढ़ते तालमेल को दिखाती है, जिसका मकसद मरीजों की सुविधाओं को बेहतर बनाना और पर्यावरण के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि सफदरजंग अस्पताल में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। अस्पताल परिसर काफी बड़ा है, ऐसे में मरीजों को एक विभाग से दूसरे विभाग तक लाने ले जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुई। इस मौके पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित तीव्र परिवर्तन के इस युग में शिक्षा राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव बनी रहेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिकल्पना की है।

उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा, अकादमिक उत्कृष्टता और आलोचनात्मक चिंतन के मूल्यों पर आधारित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के माध्यम से विश्वविद्यालय एक पसंदीदा संस्थान के रूप में उभर रहा है। उन्होंने स्नातक विद्यार्थियों को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहकर निरंतर सीखने, नवाचार और नेतृत्व को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराज्यपाल ने विद्यार्थियों से विकसित भारत और विकसित दिल्ली की निर्माण में सार्थक योगदान देने का आग्रह किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाए दी। उन्होंने कहा कि यह दिन वर्षों की मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और सपनों के साकार होने का प्रतीक है। हर विद्यार्थी की यह उपलब्धि उसके परिवार, शिक्षकों और समाज के विश्वास और सहयोग से भी जुड़ी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास, नवाचार और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, रिसर्च, स्टार्टअप, तकनीक और सामाजिक चेतना से जुड़े यही युवा विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं, जो केवल अपने भविष्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को भी नई दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं।

संपादकीय

नीट रद्द: मेहनत हारी, पेपर माफिया जीता!

देश की सबसे प्रतिष्ठित और संवेदनशील परीक्षाओं में शामिल नीट यूजी 2026 का रद्द होना केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे के टूटने का प्रतीक है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। लगभग 22 लाख छात्रों ने वर्षों की मेहनत, आर्थिक संघर्ष और मानसिक दबाव के बीच डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन पेपर लीक की आशंकाओं और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को परीक्षा रद्द करनी पड़ी।

यह फैसला भले ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया हो, लेकिन इससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं क्या भारत की परीक्षा प्रणाली अब सुरक्षित नहीं रही? क्या मेहनत से अधिक "नेटवर्क" और "पैसे" का महत्व बढ़ता जा रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर हर बड़े पेपर में लीक की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं?

पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। चाहे वह भर्ती परीक्षाएं हों या प्रवेश परीक्षाएं, हर बार लाखों युवाओं की उम्मीदें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई देती हैं। नीट जैसी परीक्षा, जो देश के मेडिकल ढांचे का भविष्य तय करती है, उसमें भी अगर पारदर्शिता पर सवाल उठने लगें तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

इस पूरे प्रकरण में सबसे दुखद पहलू उन छात्रों की मानसिक स्थिति है जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की। कई परिवारों ने बच्चों की कोचिंग के लिए कर्ज लिया, गांवों से शहरों तक संघर्ष किया, माता-पिता ने अपनी जमा पूंजी तक खर्च कर दी। अब वही छात्र दोबारा परीक्षा देने की अनिश्चितता, तनाव और डर से गुजरेंगे। यह केवल एक "री-एग्जाम" नहीं, बल्कि लाखों परिवारों पर दोबारा मानसिक और आर्थिक बोझ है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी स्वाभाविक हैं। विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है और सरकार सीबीआई जांच की बात कर रही है। लेकिन असली मुद्दा राजनीति नहीं, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता है। हर बार जांच, गिरफ्तारी और आश्वासन की बातें होती हैं, लेकिन पेपर माफिया का नेटवर्क खत्म क्यों नहीं होता? यदि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले डिजिटल माध्यमों से राज्यों तक पहुंच सकता है, तो इसका अर्थ है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर सेंध मौजूद है।

यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या परीक्षा संचालन पूरी तरह केंद्रीकृत एजेंसियों पर छोड़ देना पर्याप्त है? आधुनिक तकनीक के इस दौर में एन्क्रिप्टेड डिजिटल सिस्टम, ए आई आधारित निगरानी, लाइव ट्रैकिंग और प्रश्नपत्र वितरण की मल्टी-लेयर सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं क्यों प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहीं? जब बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल मॉडल पर काम कर सकते हैं, तो देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं क्यों नहीं? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या केवल परीक्षा रद्द कर देना समाधान है? दोषियों को पकड़ना और कठोर सजा देना उतना ही जरूरी है। जब तक पेपर लीक को "संगठित अपराध" मानकर उसके खिलाफ तेज और उदाहरणात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे गिरोह लगातार सक्रिय रहेंगे। केवल छोटे एजेंटों को पकड़ने से समस्या खत्म नहीं होगी; उन प्रभावशाली नेटवर्क तक पहुंचना होगा जो शिक्षा को कारोबार बना चुके हैं।

सरकार के लिए यह समय आत्ममंथन का है। युवाओं का विश्वास खोना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत होता है। देश का युवा अगर यह महसूस करने लगे कि उसकी मेहनत का मूल्य नहीं है, तो यह केवल शिक्षा संकट नहीं बल्कि सामाजिक असंतोष का कारण भी बन सकता है।

नीट 2026 का रद्द होना एक चेतावनी है यदि अब भी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार नहीं किए गए, तो आने वाले समय में "प्रतिभा" और "परिश्रम" पर से समाज का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। देश को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी मेहनत से बनें, न कि "पेपर लीक" के सहारे। भारत के युवाओं को सिर्फ नई परीक्षा तारीख नहीं, बल्कि यह भरोसा चाहिए कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है।

केजरीवाल के लिए अंतिम अवसर

मनोज कुमार मिश्र

आआपा और उसके सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए बने हैं इसे इस राजनीतिक पार्टी के 14 साल के इतिहास ने साबित किया है। समाजसेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के सहारे राजनीति में आने वाले केजरीवाल ने वह सभी काम किए जो इस देश के आम राजनेता करते रहे हैं या इसके लिए राजनेता बदनाम हैं।

अगले साल देश के सात राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह हैं-पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इनमें से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलावा सभी पांचों राज्यों में अभी भाजपा की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है और दिल्ली में सत्ता जाने के बाद आम आदमी पार्टी(आआपा) केवल पंजाब में सत्ता में है। भाजपा तो हर राज्य में चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति में लगी हुई है लेकिन इस बार उसका फोकस पंजाब जीतने पर होने वाला है। एक तो हिमाचल प्रदेश वैसे ही भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है, दूसरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार शुरू से ही गिरते-पड़ते चल रही है। इसलिए आम धारणा है कि जब भी चुनाव होंगे भाजपा आसानी से चुनाव जीत जाएगी।

भाजपा पंजाब चुनाव को उसी तरह लड़ने वाली है जिस तरह से उसने पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा और ममता बनर्जी जैसी जमीन से जुड़ी और लड़ाकू महिला को पराजित करके पहली बार जीत हासिल की। चुनाव तो पिछले महीने भी पांच राज्यों के विधानसभा के हुए थे। भाजपा पहले से सत्ता में काबिज असम और पुडुचेरी में जीत हासिल की। केरल में वोट औसत बढ़ने के साथ भाजपा को तीन सीटें मिली। तमिलनाडु में भी भाजपा को वोट औसत बढ़ा। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धि यह रही कि देश में विपक्षी राजनीति का झंडा थामने वाले नेताओं में से ममता बनर्जी की तरह तमिलनाडु मुख्यमंत्री रहे एम के स्टालिन सत्ता से बाहर हो गए। पंजाब चुनाव नतीजे आआपा के पक्ष में न आने पर न केवल आआपा के बिखरने के साथ-साथ बल्कि आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पारी का समापन भी होने का खतरा है।

आआपा और उसके सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए बने हैं इसे इस राजनीतिक पार्टी के 14 साल के इतिहास ने साबित किया है। समाजसेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के सहारे राजनीति में आने वाले केजरीवाल ने वह सभी काम किए जो इस देश के आम राजनेता करते रहे हैं या इसके लिए राजनेता बदनाम हैं। कई मामलों में तो केजरीवाल ने परंपरागत दलों के नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। सत्ता में आने के लिए उन्होंने जो वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद सारे आचरण उसके उलट किए। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद भी उनका व्यवहार नहीं बदला। 2025 के विधानसभा चुनाव में जो आरोप मुद्दे बने उसमें शराब घोटाला से लेकर अपने सरकारी आवास को करोड़ों खर्च करके शीश महल बनवाना प्रमुख रहे। बावजूद इसके पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मिले सरकारी आवास में उन पर फिर से लाखों रुपये लगाने का आरोप लगा है। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने 1974 के बिहार छात्र आंदोलन और उससे लगे आपातकाल के खिलाफ देश भर में हुए आंदोलन को फिर से दोहरा दिया था। पहला विवाद को अन्ना हजारे के मना करने के बावजूद 26 नवंबर,2012 को राजनीतिक पार्टी आआपा बनाने पर हुआ। हजारों पढ़े-लिखे नौजवान देश-विदेश की नौकरी छोड़कर और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंची हैसियत और मानदंड रखने वालों ने उस आंदोलन में अपना सभी कुछ न्योछावर कर दिया था। सत्ता में आने और अपना असली रंग दिखाने के बाद वही लोग एक-एक करके लोग अलग होने लगे। कुछ को केजरीवाल ने अपमानित करके निकाला। इसकी लंबी श्रृंखला बनती जा रही है। अभी सबसे बड़ा झटका आआपा के बड़े नाम राघव चड्ढा और संदीप पाठक के साथ दस में से सात राज्य सभा सदस्यों का पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने से लगा है। उनमें से एक स्वाति मालीवाल तो काफी समय से तो केवल तकनीकी तौर पर आआपा में थी वे अपने साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास में मारापीट होने के बाद से ही अलग हो गई थी। अब आआपा के साथ तीन राज्यसभा और तीन लोकसभा सदस्य हैं।

इन चौदह सालों के घटनाक्रम ने एक बात तो साबित कर दी कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। भाजपा और कांग्रेस विरोधी अनेक बुद्धिजीवियों के प्रभाव में आकर केजरीवाल ने 2014 में देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ना तय किया। भारी पराजय के बाद अपने लोगों के गुस्सा से बचने के लिए जमानत तुड़वाकर जेल गए। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी सफलता के बावजूद रामलीला मैदान में दूसरी बार मुख्यमंत्री की सफल लेते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता से जनादेश उनकी सेवा करने के लिए मिला है, वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। तब से लेकर अब तक उनके बयान और दावों में लगातार बदलाव होते ही गए। जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें केजरीवाल की तुलना विदेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन चलाकर सीधे छात्र आंदोलन से असम गण परिषद राजनीतिक दल बनाकर विधानसभा चुनाव जीतकर 1985 में असम के मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल कुमार महंत से की जाने लगी है।

आज की तारीख में महंत की असम की राजनीति में कोई चर्चा तक नहीं होती है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाकर 2013 में होने वाले दिल्ली विधान सभा चुनाव लड़ना तय किया। पहले ही चुनाव में ही बिजली-पानी फ्री का मुद्दा कारगर हुआ। आआपा को 70 सदस्यों वाली विधानसभा में करीब 30 फीसद वोट और 28 सीटें मिली। भाजपा करीब 34 फीसद वोट के साथ 32 सीटें जीती और दिल्ली में 15 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस को 24.50 फीसद वोट के साथ केवल आठ सीटें मिली। भाजपा के मना करने पर आआपा ने कांग्रेस से बिना मांगे समर्थन से सरकार बनाई और नियम का पालन किए बिना लोकपाल विधेयक विधानसभा में पेश करने से रोके जाने के खिलाफ 49 दिन पुरानी सरकार ने इस्तीफा दिया।

2014 के लोकसभा चुनाव में आआपा ने देश भर में चुनाव लड़ना तय किया। खुद केजरीवाल भाजपा के प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के खिलाफ बनारस चुनाव लड़ने पहुंच गए। वे तो बुरी तरह से हारे ही आआपा के ज्यादातर प्रमुख नेता लोकसभा चुनाव लड़े और पराजित हुए। केवल पंजाब में चार सीट आआपा जीत पाई। बाद में उसमें से दो सांसद आआपा से अलग हो गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल अभी के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव जीते। 2024 में उसे केवल पंजाब में ही तीन सीटें मिली। 2014 के चुनाव में केजरीवाल ने बड़ा सपना देखा था, वे परिणाम से इतने आहत हुए थे कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत करने के लिए जबरन जमानत तुड़वाकर जेल गए। इतना ही नहीं एक-एक करके पार्टी के दिग्गजों-पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव, प्रो. आनंद कुमार इत्यादि को पार्टी से बाहर किया। बाद में कुमार विश्वास समेत अनेक दिग्गज नेता बाहर हुए। यह सिलसिला आज भी जारी है। कहा जाता कि आआपा में वही रह सकता है जो केजरीवाल के किसी फैसले पर सवाल न उठाए। बावजूद इसके आआपा को कई बड़ी सफलता मिल गई।

कांग्रेस की कमजोरी और भाजपा की अधूरी तैयारी के चलते और बिजली-पानी फ्री करने के वादे ने आप को 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में रिकार्ड 54 फीसदी वोट के साथ 67 सीटों पर जीत दिलवा दी। उस चुनाव के बाद पार्टी में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कद और बढ़ गया। दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने दिल्ली से बाहर पार्टी को न ले जाने का घोषणा कर दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि पार्टी को वोट उनके नाम से मिलते हैं। 2020 के दिल्ली विधान सभाचुनाव में फिर उन्होंने रिकार्ड 54 फीसद वोट के साथ 62 सीटें जीती। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में तो आआपा को कोई सफलता नहीं मिली लेकिन पंजाब में बेहतर नतीजे मिले। 2017 के चुनाव में 117 सीटों की विधानसभा में आआपा को 20 सीटें मिली। 2022 में उसे न केवल 92 सीटें मिली और उसकी दिल्ली से बाहर सरकार बनी। गुजरात और गोवा में चुनाव लड़कर आआपा 10 अप्रैल,2023 को अखिल भारतीय पार्टी बन गई।

सत्ता ने उन्हें आम आदमी से खास आदमी बना दिया। सुरक्षा के भारी तामझाम से उनकी लोगों से दूरी बढ़ी और जिस वीआईपी कल्चर का विरोध करके राजनीति में आए उसी कल्चर के प्रतीक बन गए। शराब घोटाले में कई बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद खुद केजरीवाल जेल गए। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने अपने को प्रताड़ित करने का मुद्दा बनाने की असफल कोशिश की। 70 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में भाजपा 48 सीटों के साथ 27 साल बाद सत्ता में लौटी। आआपा को 22 सीटें मिली। मतों का अंतर केवल दो फीसद का था। पहली बार आआपा 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव जीती थी। उसे 250 में से134 सीटें मिली थी। भाजपा को 104 सीटें मिली थी। केन्द्र में भाजपा की सरकार होने का लाभ उसे मिलता रहा। बहुमत के बावजूद महीनों कवायद के बाद आआपा का मेयर बना। इन ढाई सालों में आआपा के पार्षद भाजपा में आते रहे। इतना ही नहीं आआपा में जाकर पार्षद बने 16 निगम पार्षद अलग दल बनाकर आप से अलग हो गए। निगम में दलबदल विरोधी कानून नहीं लागू है। अब निगम में भी भाजपा बहुमत में है। आआपा पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी है । वह न तो किसी विचारधारा से जुड़ी है, न जाति आधारित या कैडर आधारित पार्टी है। दिल्ली में सरकार जाने के बाद को पार्टी के साथ मुट्ठी भर लोग दिखते हैं। अब केवल पंजाब में आआपा की सरकार है। पंजाब सरकार के खिलाफ भी पार्टी में आवाज उठने लगी है।

पेट्रोल संकट का दीर्घकालीन समाधान भारत के पास है

कुलभूषण उपमन्यु

देश में 2025 की पशु गणना के अनुसार 193.50 करोड़ गोवंश और 109.85 करोड़ भैंस हैं। कुल 303.35 करोड़ ऐसा पशु धन है जिनके गोबर से मीथेन गैस बनाई जा सकती है। एक किलो मीथेन गैस बनाने के लिए लगभग 30 किलो गोबर चाहिए, जो हमें दो पशुओं से दैनिक प्राप्त हो सकता है। इस तरह 150 करोड़ किलो गैस प्रतिदिन बनाई जा सकती है। साल में कुछ कमीबेशी को छोड़ दें तो 300 दिन का गिनते हैं। इससे 45000 करोड़ किलो गैस प्रतिवर्ष बनाई जा सकती है।

ईरान, इजराइल-अमेरिका युद्ध ने वैश्विक स्तर पर खनिज तेल आधारित ऊर्जा व्यवस्था को डांवाडोल कर दिया है। भारतवर्ष पर इसका खासा असर होना स्वाभाविक है क्योंकि हमारी 85 फीसद ऊर्जा जरूरतें आयात के माध्यम से ही पूरी होती हैं और इसका बड़ा भाग मध्य पूर्वी देशों से ही आता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री नौवहन में युद्ध के कारण आई रुकावट के चलते यह स्पष्ट हो चुका है कि इस तरह की स्थितियां देश की घरेलू, औद्योगिक, और सैनिक जरूरतों के लिए घातक साबित हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में युद्ध के चलते खनिज तेल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं।

सरकार ने अभी तक तो घरेलू ऊर्जा जरूरतों पर बढ़ी हुई कीमतों का उतना असर नहीं होने दिया है किन्तु लंबे समय तक ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। इस समस्या के दीर्घकालीन समाधान को ध्यान में रख कर ही सरकार ने एथनोल को पेट्रोल में मिला कर पेट्रोलियम पदार्थों की मांग कम करने का प्रयास शुरू किया है। एथनोल के प्रयोग को लगातार बढ़ाते जाने की योजना पर काम हो रहा है, लेकिन इसकी भी सीमा है जिससे आगे एथनोल उत्पादन संभव नहीं होगा। हमारे पास और भी संसाधन हैं जिनके योजनाबद्ध उपयोग से हम उर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में बड़ा योगदान कर सकते हैं। हमारे पास कृषि अपशिष्ट और गोबर का प्रचुर भंडार है, जिससे मीथेन, सीएनजी, पीएनजी बना कर खनिज तेल की आयात जरूरतों को कम किया जा सकता है। फिलहाल उपलब्ध गोबर का उपयोग करने पर क्या स्थितियां बनेंगी इस पर विचार करते हैं।

देश में 2025 की पशु गणना के अनुसार 193.50 करोड़ गोवंश और 109.85 करोड़ भैंस हैं। कुल 303.35 करोड़ ऐसा पशु धन है जिनके गोबर से मीथेन गैस बनाई जा सकती है। एक किलो मीथेन गैस बनाने के लिए लगभग 30 किलो गोबर चाहिए, जो हमें दो पशुओं से दैनिक प्राप्त हो सकता है। इस तरह 150 करोड़ किलो गैस प्रतिदिन बनाई जा सकती है। साल में कुछ कमीबेशी को छोड़ दें तो 300 दिन का गिनते हैं। इससे 45000 करोड़ किलो गैस प्रतिवर्ष बनाई जा सकती है।

इसको टन में बदल लें तो 45 करोड़ टन हुए। एक सिलिंडर में 15 किलो गैस के हिसाब से एक टन से 66 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। 45 करोड़ टन से 2970 करोड़ सिलेंडर भरे जाएंगे। देश की आबादी को 140 करोड़ मानते हुए औसत पांच प्राणियों का परिवार मानते हुए 28 करोड़ परिवार हुए। यदि हर महीने प्रति परिवार एक सिलेंडर की खपत मान कर चलें तो 12 महीने में 336 करोड़ सिलेंडर की खपत होगी। जबकि हमारे पास संसाधन 2970 करोड़ सिलेंडर भरने की है। यानि इस क्षमता का 15-20 प्रतिशत दोहन भी कर लिया जाए तो घरेलू खपत को पूरा किया जा सकता है और इससे आगे व्यवसायिक खपत की भी गुंजाइश रह जाती है।

हर घर में गोबर गैस प्लांट बनाना शायद संभव नहीं होगा किन्तु कुछ में तो संभव होगा। शेष संसाधन को वाणिज्यिक स्तर पर बड़े और आधुनिक तकनीक पर कार्य करने वाले गोबर गैस प्लांट बना कर ऊर्जा सुरक्षा की ओर आत्मनिर्भर कदम बढ़ाया जा सकता है, और आयात बिल और विदेशी मुद्रा को भी बचाया जा सकता है। जिस तरह एथनोल उत्पादन कार्य को गंभीरता से तेज गति से बढ़ाया गया है यदि उसी भावना से गोबर गैस उत्पादन को भी वाणिज्यिक स्तर पर प्रोत्साहन दे कर आगे बढ़ाया जाए तो बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है।

इससे किसानों को भी गोबर उपलब्ध करवाने के बदले अतिरिक्त कमाई हो सकती है। इस प्रक्रिया में गैस तो निकल जाती है, शेष गोबर, डाईजेस्टर में अच्छी तरह सड़ कर बाहर आता है जो ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण खाद होता है। इसके अलावा फसलों के अपशिष्ट, पराली या गेहूं के अपशिष्ट भी सीएनजी, पीएनजी बनाने के लिए उपयोग कर लिए जाएं तो काफी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस के आयात में कमी आ सकती है।

फसल अपशिष्ट से सीएनजी बनाने के कुछ संयंत्र तो शुरू भी हो चुके हैं। इन सब कामों के लिए तकनीक तो हमारे पास उपलब्ध ही है केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से आरंभ करने की बात है। फसल अपशिष्ट इस तरह इस्तेमाल कर लेने से उन्हें जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारियों और असमय मौतों से भी बचा जा सकता है। इस कार्य में भी कुछ कठिनाइयां तो आएंगी किन्तु अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गुलामी से मुक्ति भी तो मिलेगी। ***(लेखक, पर्यावरणविद और हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष हैं)***

भगत सिंह के मस्तिष्क शहीद सुखदेव को हमने कितना याद रखा?

इतिहास की एक अजीब फितरत होती है। वह कभी-कभी किसी महानायक के महाकाय प्रभाव में उसके सबसे बड़े मददगार और हमसफर को परदे के पीछे धकेल देता है। 23 मार्च 1931 की शाम को जब लाहौर की सेंट्रल जेल में तीन नौजवान फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे, तब भारत की जुबान पर एक नाम ऐसा चढ़ा कि बाकी दो नाम उसके साए में थोड़े सिमट गए। हम बात कर रहे हैं क्रांति के तीन शहीदों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। इस अटूट तिकड़ी में भगत सिंह क्रांति का चमकता हुआ चेहरा थे और राजगुरु अचूक निशानेबाज, लेकिन इन सबके पीछे जो बेहद शांत, गंभीर और तीखा दिमाग काम कर रहा था, वह नाम था क्रांतिकारी सुखदेव थापर का। आज 15 मई को उनकी जयंती पर यह सोचना बहुत जरूरी है कि इस जमीनी रणनीतिकार को हमने अपनी यादों और इतिहास में कितना स्थान दिया। पंजाब के लायलपुर में जन्मे सुखदेव और भगत सिंह सिर्फ साथ में देश के लिए लड़ने वाले साथी नहीं थे, बल्कि दोनों के बीच एक बेहद गहरी और बेमिसाल दोस्ती थी। लाहौर के नेशनल कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ यह साथ देश की आजादी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जब देश में नौजवानों को एकजुट करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ, तो पंजाब की पूरी जिम्मेदारी सुखदेव को सौंपी गई। यहीं से उनके संगठन बनाने और उसे चलाने के लाजवाब हुनर की शुरुआत होती है। वे कागजों पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें चुपचाप जमीन पर सच कर दिखाने में माहिर थे।अक्सर स्कूल-कॉलेज की किताबों में सुखदेव को भगत सिंह के एक साथी के रूप में ही दिखाकर छोड़ दिया जाता है, जो उनके साथ एक तरह की नाइंसाफी है। असलियत तो यह है कि ब्रिटिश पुलिस ने जब अदालत में मशहूर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा दर्ज किया था, तो उसकी पहली एफआईआर में आरोपी नंबर एक कोई और नहीं, बल्कि खुद सुखदेव थापर थे। अंग्रेज सरकार भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस पूरी सशस्त्र क्रांति की डोर असल में किसके हाथ में है।

लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब जेपी सांडर्स को सजा देने की योजना बनी, तो उसके पीछे असली दिमाग सुखदेव का ही था। उन्होंने ही राजगुरु और भगत सिंह को इस बड़े मिशन के लिए तैयार किया, उनके छिपने के गुप्त ठिकाने ढूंढे और काम पूरा होने के बाद वहां से सुरक्षित निकलने का पूरा रास्ता साफ किया। सुखदेव कभी वाहवाही लूटने या अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले नेता नहीं थे। वे खुद को हमेशा पीछे रखकर संगठन को मजबूत करते रहे, गलियों-कस्बों में जाकर युवाओं के दिलों में आजादी की अलख जगाते रहे। सुखदेव के बारे में इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जो अमूमन चर्चाओं से गायब रहता है। जेल की कालकोठरी में रहते हुए जब राजनीतिक कैदियों के मानवीय अधिकारों का हनन हुआ, तब सुखदेव ने जेल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने जेल के भीतर बिना अन्न-जल के लगातार 63 दिनों तक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। इस कड़े और जानलेवा उपवास ने ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर रवैये को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि वे सिर्फ बम और पिस्तौल की रणनीति ही नहीं जानते थे, बल्कि वैचारिक और सत्याग्रही मोर्चे पर भी उनका कोई सानी नहीं था। उनकी सोच कितनी खुली और साफ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे किसी भी तरह के अंधविश्वास और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को एक खुला खत लिखा था, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं की दशा पर बेहद कड़े और सीधे सवाल पूछे थे। यह चिट्ठी बताती है कि उनका दिल देश के भविष्य के लिए कितना तड़पता था। लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारे देश के नीति-निर्माताओं और इतिहासकारों ने सुखदेव के योगदान को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे। हमने उन्हें सिर्फ एक शहीद तिकड़ी के हिस्से के रूप में याद रखा। फिल्मों से लेकर बड़े-बड़े सरकारी विज्ञापनों तक में उन्हें वह मुख्य स्थान कभी नहीं मिल पाया। सुखदेव का जीवन हमें सिखाता है कि असली काम शोर मचाकर नहीं, बल्कि शांत रहकर किया जाता है। सुखदेव सिर्फ 23 साल की उम्र में देश पर न्योछावर हो गए। 15 मई का यह दिन देश के उस सच्चे सिपाही को सलाम करने का दिन है जिसने परदे के पीछे रहकर आजादी की सबसे बड़ी इबारत लिखी थी।

नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में संलिप्त परीक्षा माफिया को बख्शा नहीं जाएगा : भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी।

भाजपा ने कहा कि सरकार ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता से लिया है तथा पार्टी ने छात्रों और अभिभावकों को इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, खासकर इस परीक्षा माफिया को जो हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है।

मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट-यूजी, 2026 परीक्षा को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दिया। मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रवेश परीक्षा रद्द होने से 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में अनिश्चितता का माहौल है।इस मुद्दे को संवेदनशील और दुखद'' बताते हुए पात्रा ने कहा कि यह न केवल 22 लाख छात्रों से संबंधित है, बल्कि उनके माता-पिता की भावनाओं को भी प्रभावित करता है। भाजपा सांसद ने कहा, जैसे ही भंडाफोड़ करने वाले एक व्यक्ति ने इस मुद्दे को उजागर किया, बिना किसी झिझक या टालमटोल का रवैया अपनाए बिना तुरंत कार्रवाई शुरू की गई।

दिल्ली में मौजूद रिमोट कंट्रोल से चलेगी केरल की कांग्रेस सरकार : भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वी डी सतीशन को केरल का अगला मुख्यमंत्री चुने जाने संबंधी फैसले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह कदम पार्टी के भीतर आंतरिक कलह को उजागर करता है और इससे पता चलता है कि यह रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार होगी।

भाजपा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री का चयन कांग्रेस विधायकों की पसंद नहीं बल्कि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) का निर्णय था जो संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है।

कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के शीर्ष और प्रदेश इकाई के नेताओं के साथ लंबी मंत्रणा के बाद केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सतीशन के नाम पर मुहर लगाई।

केरल के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों अजय माकन और मुकुल वासनिक के साथ यहां पार्टी कार्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस की केरल प्रभारी दीपा दासमुंशी ने सतीशन के नाम की घोषणा की। सतीशन के अलावा कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल थे।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई पर यह निर्णय थोपा है।

उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला नयी दिल्ली में हुआ है, न कि केरल में। यह घोषणा दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय से की गई, जिससे पता चलता है कि यह 'रिमोट कंट्रोल से संचालित सरकार' होगी। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि केरल में नेतृत्व के चयन को लेकर गांधी परिवार में मतभेद था। उन्होंने कहा कि सतीशन का चयन प्रियंका गांधी वाद्रा के दबाव के कारण हुआ, जो किसी भी कीमत पर राहुल गांधी की पसंद के उम्मीदवार के.सी. वेणुगोपाल को नहीं चाहती थीं। उन्होंने दावा किया, प्रियंका गांधी वाद्रा के.सी. वेणुगोपाल के सख्त खिलाफ थीं। दरअसल, केरल में सत्ता किसके हाथ में होगी, इसे लेकर परिवार में जबरदस्त विवाद हुआ।

पूनावाला ने केरल में कांग्रेस नेता की घोषणा में देरी के लिए आंतरिक मतभेदों और गठबंधन सहयोगियों के दबाव को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, 11 दिन के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने वी डी सतीशन जी को अपना नेता घोषित कर दिया है और इसका मतलब है कि वह अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा दो तरह के दबावों के चलते हुआ है। जमात और आईयूएमएल ने कांग्रेस को कड़ी चेतावनी दी थी। इसलिए यह स्पष्ट रूप से मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव है। भाजपा प्रवक्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकारों का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि गुटबाजी और आपसी खींचतान की समस्या केरल में भी पार्टी को परेशान करती रहेगी।

उन्होंने दावा किया, यह कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मॉडल जैसा ही होगा। वहां डी.के. शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच टकराव है। यहां मुकाबला सतीशन बनाम के सी वेणुगोपाल बनाम चेन्निथला बनाम शशि थरूर के बीच होगा। यहां चार-पांच दावेदार होंगे जो लगातार माहौल को अस्थिर करते रहेंगे। पूनावाला ने कहा कि इसी तरह के आंतरिक संघर्षों ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारों को प्रभावित किया।

शिवराज चौहान ने अपने काफिले का आकार घटाया

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को अपने काफिले के आकार को घटाकर तीन गाड़ियों का कर दिया और अधिकारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'सात अपीलों' को लागू करने के उपायों के तहत उठाया गया है, जिनका उद्देश्य ईंधन का जिम्मेदारी से उपभोग करना है।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, चौहान ने विभागों से दो दिन के भीतर 'घर से काम' (डब्ल्यूएफएच) नीति पर एक कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा और कर्मचारियों से 'कार पूलिंग' अपनाने का आग्रह किया। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा तभी की जाएगी जब यह बिल्कुल आवश्यक हो और अधिकांश बैठकें वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाएंगी। अधिकारियों और कर्मचारियों से गैर-जरूरी सोना खरीदने से बचने और कम से कम पांच अन्य व्यक्तियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया। कृषि के क्षेत्र में, मंत्री ने हर गांव में एक समिति गठित करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित उपयोग और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा।

चौहान ने कहा कि खाद्य तेलों का उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए और उन्होंने पांच-पांच परिवारों के समूहों के बीच एक जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मंत्री स्तर पर मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, और साथ ही घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि अनावश्यक विदेश यात्रा से बचा जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सरकारी बैठकों में स्थानीय उत्पादों, मोटे अनाज (मिलेट्स) और स्वदेशी खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाएगी। 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारतीय ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आईसीएआर, कृषि शिक्षा विभाग और भूमि संसाधन विभाग संयुक्त रूप से एक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया तीन दिवसीय सिक्किम दौरे पर

सिलीगुड़ी, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिन के सिक्किम दौरे पर गुरुवार शाम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचें। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात में सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में तेजी से विकास हो रहा है और सिक्किम देश के सबसे बेहतर राज्यों में शामिल है, खासकर ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति भी शिरकत करेंगे। राज्य में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन ऐतिहासिक है और यह सरकार आम लोगों के हित में काम करेगी। साथ ही उन्होंने "विकसित भारत" के लक्ष्य

नेतानार सीआरपीएफ कैंप बस्तर का पहला जन सुविधा केंद्र बनेगा

जगदलपुर, एजेंसी।

बस्तर में पिछले चार दशक से नक्सल मोर्चे पर तैनात अर्धसैनिक बलों के बस्तर से लौटने का सिलसिला जल्द ही शुरू होने वाला है।

नक्सल मुक्त बस्तर होने के बाद इन सुरक्षा कैंपों को स्थानीय ग्रामीणों के लिए जन सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा गृहमंत्री अमित शाह ने की थी।

इसी कड़ी में आगामी 18 मई को 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर पहुंच रहे गृहमंत्री शाह नेतानार सीआरपीएफ कैंप को बस्तर का पहला जन सुविधा केंद्र घोषित कर इसका उद्घाटन करेंगे।

दरअसल, यह इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। नक्सलियों ने नेतानार के आसपास के इलाकों में कई बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया, जिसके बाद यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कैंप स्थापित करने के बाद इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधि कम होने के साथ अब यह इलाका पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। ऐसे में अब इस कैंप को बस्तर का पहला जन सुविधा केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि 31 मार्च के बाद बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में नक्सल गतिविधि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिन नक्सल इलाकों में सुरक्षा कैंप खोले गए थे।

सार समाचार

असम में 21 करोड़ की हेरोइन व अफीम के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी, एजेंसी। असम में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कामरूप पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अमीनगांव में एक बस से करीब 21 करोड़ 36 लाख मूल्य की हेरोइन और अफीम बरामद की है। इस मामले में पांच कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस के सीपीआरओ ने गुरवार को बताया कि, गुप्त सूचना मिली थी कि मणिपुर के क्वाकटा से पड़ोसी राज्य की ओर जा रही बस संख्या एएस 06 एसी 7555 के जरिए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना में यह भी बताया गया था कि बस में कोई सामान्य यात्री नहीं है और उसमें केवल तस्कर सवार हैं।

फाजिल्का बॉर्डर पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन

चंडीगढ़, एजेंसी। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशा और हथियार तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन सीमा पार से ड्रोन गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार देर रात फाजिल्का के भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार गांव चक्क बाजीदा के खेतों में ड्रोन गिरने की सूचना मिलने के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

इस दौरान खेतों से एक ड्रोन बरामद किया गया। इस मामले में थाना सदर जलालाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस चौकी घुबाया के इंचार्ज गुरनाम सिंह ने बताया कि बीएसएफ से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। उन्होंने बताया कि एक किसान के खेत में गेहूं के नाड़ के बीच ड्रोन पड़ा मिला, जिसे कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह ड्रोन सीमा पार से हेरोइन की खेप गिराने के बाद वापस लौट रहा था, लेकिन बैटरी खत्म होने या किसी तकनीकी खराबी के कारण खेतों में गिर गया। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्रोन किसके लिए भेजा गया था।

असम में घुसपैठ कर रहे 12 बांग्लादेशियों को रोका गया : हिमंत

गुवाहाटी, एजेंसी।

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने गुरुवार को कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और असम पुलिस ने 12 कथित घुसपैठियों को असम में घुसपैठ करने से रोक दिया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह अभियान बीती मध्य रात्रि के ठीक बाद चलाया गया था, जो राज्य में अवैध घुसपैठ पर चल रही कड़ी कार्रवाई का ही एक हिस्सा है।

डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि करीब 12:20 बजे, असम पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर घुसपैठियों की हलचल को रोका और 12 अवैध लोगों को असम में घुसने से रोक दिया। हालांकि, राज्य के किस हिस्से से घुसपैठ हो रही थी, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि असम सरकार अवैध प्रवासन और घुसपैठ के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव के खिलाफ अपनी सख्त ₹जीरो टॉलरेंस₹ की नीति को जारी रखेगी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब असम सरकार सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय चिंताओं पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है।

महाराष्ट्र विधान परिषद में दस नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ

मुंबई, एजेंसी। विधान परिषद के द्वि-वार्षिक चुनाव में 9 और उप-चुनाव में एक सहित कुल 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को विधान भवन के मध्यवर्ती सभागृह में सम्पन्न हुआ। विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें भाजपा से 6, और अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित कई मंत्री उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक जिशान सिद्दीकी ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली।

नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक : दिल्ली की अदालत ने पांच आरोपियों को सात दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली की एक अदालत ने नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की सात दिन की हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई के मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत ने केंद्रीय एजेंसी की अर्जी पर सुनवाई की जिसमें इस मामले में पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सभी पांच आरोपियों को पूछताछ के लिए सात तक उसकी हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया था।

सीबीआई ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा तीन मई को

आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में कथित तौर पर संलिप्त होने के आरोपों में पांचों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की पहचान नासिक (महाराष्ट्र)के शुभम खैरनार, जयपुर (राजस्थान) के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल और गुरुग्राम (हरियाणा) के यश यादव के रूप में हुई है।

विभिन्न राज्यों की स्थानीय अदालतों से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया।

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 परीक्षा तीन मई को आयोजित की गई थी। इसके प्रश्न पत्र के लीक होने की खबरों के बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच शुरू की।

एनटीए ने गत मंगलवार को नीट-यूजी 2026 को रद्द करने की घोषणा की और कहा कि परीक्षा बाद में घोषित की जाने वाली तिथियों पर पुनः आयोजित की जाएगी।

सीबीआई की ओर से आरोपियों की हिरासत लेने के लिए दाखिल अर्जी में दलील दी गई कि परीक्षा से पहले व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ प्रारूप में प्रश्न प्रसारित किए गए जिससे परीक्षा की सुचिता भंग हुई।

उच्च शिक्षा विभाग (एनटीए प्रभाग) के निदेशक वरुण भारद्वाज की शिकायत पर 12 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मणिपुर हिंसा की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट जारी की जाए: कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस ने मणिपुर में हुई हिंसा की हालिया घटनाओं की निंदा की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के जान-माल की रक्षा करने में विफल रही है।

पार्टी सांसद ए. विमल अकोइजम ने यह भी कहा कि सरकार को मणिपुर हिंसा की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और सशस्त्र समूहों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बीते बुधवार को संदिग्ध उग्रवादियों के हमले में चर्च के तीन पदाधिकारियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह घटना कोट्जिम और कोटलेन गांवों के बीच उस समय घटी जब थाडो बैपटिस्ट एसोसिएशन (टीबीए) के सदस्य एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद चुराचांदपुर से लौट रहे थे।

अकोइजम ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमारी पार्टी ने लगातार मांग की है कि सरकार मणिपुर के लोगों के जान-माल की रक्षा करे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही है। हम इस हिंसा और भारत सरकार के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी यह मांग भी है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार को मणिपुर में हिंसा रोकने की फिक्र नहीं है। अकोइजम ने कहा, हम भारत सरकार से उस जांच आयोग की रिपोर्ट जारी करने की अपील करते हैं, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान हैं। उनका कहना था कि इस हिंसा के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए और इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।

अकोइजम ने कहा, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे सशस्त्र समूहों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में हम मांग करते हैं कि भारत सरकार मणिपुर के नागरिकों के जान-माल की रक्षा करे।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए चार जून, 2023 को जांच आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मूल रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा कर रहे थे।

आयुष मंत्रालय और डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के बीच करार

नई दिल्ली, एजेंसी। आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के बीच गुरुवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस साझेदारी का उद्देश्य उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित भाषा तकनीक के माध्यम से आयुष ज्ञान प्रणालियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में तेज़ी से अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन करना है।

यह पहल आयुष मंत्रालय के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सेवाओं में भारत की राष्ट्रीय भाषा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 'भाषिणी प्लेटफॉर्म' को एकीकृत करने का कार्य करेगी।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे

गांधीनगर, एजेंसी।

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुरुवार को ट्रेन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने ईंधन बचत और स्वदेशी अपनाने का संदेश देते हुए कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से गुरुकुल कुरुक्षेत्र तक साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक किया।

राज्यपाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी वस्तुओं की खरीद कर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए।

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक देश में ईंधन की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक उन्होंने राज्य के कार्यक्रमों के लिए हवाई यात्रा और हेलिकॉप्टर का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया है। साथ ही अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी सीमित कर दी है।

राज्यपाल गुजरात से कुरुक्षेत्र तक ट्रेन से यात्रा कर सुबह करीब 9:30 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां गुरुकुल परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया।

इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मार्ग तक साइकिल यात्रा की और गुरुकुल पहुंचे। इस यात्रा में उनके साथ ओएसडी डॉ. राजेंद्र विद्यालंकार, गौरव आर्य और लगभग 200 साइकिल सवार शामिल हुए।

मप्र : पटाखा कारखाने में विस्फोट से तीन मजदूरों की मौत

देवास/इंदौर, एजेंसी।

मध्यप्रदेश के देवास जिले में एक पटाखा कारखाने में हुए धमाके में कम से कम तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 श्रमिक घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कारखाने के मालिक को सख्त प्रावधानों वाले राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया है और घटना का कारण जानने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ऋतुराज सिंह ने टोंक कलां क्षेत्र में संचालित पटाखा कारखाने के लाइसेंसी मालिक अनिल मालवीय पर एनएसए लगा दिया है और उसे गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई पटाखा लाइसेंस का गलत तरीके से उपयोग करने और इसकी नियम-शर्तों के उल्लंघन को लेकर पुलिस अधीक्षक की सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। उन्होंने बताया कि मालवीय के नाम जारी पटाखा लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है।

राज्य के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती मजदूरों के हाल-चाल जाने। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि कारखाना मालिक को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

ममता बनर्जी ने अदालत में कहा कि वह पहली बार कलकत्ता उच्च न्यायालय में बहस कर रही हैं

वकील के पोशाक में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

कोलकाता, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचीं और 2021 के विधानसभा चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामले में अदालत के समक्ष पक्ष रखा। वह सुबह वकील के परिधान में उच्च न्यायालय परिसर पहुंचीं और मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं।

ममता बनर्जी ने अदालत में कहा कि वह पहली बार कलकत्ता उच्च न्यायालय में बहस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1985 में बार काउंसिल में उनका पंजीकरण हुआ था और तब से वह सदस्यता का नवीनीकरण कराती रही हैं।

अदालत में ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद राज्य में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि विवाहित महिलाओं को दुष्कर्म की धमकियां दी जा रही हैं, घरों में लूटपाट और आगजनी हो रही है तथा पुलिस कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अनुमति मिलने पर इन शिकायतों को अतिरिक्त हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करें और राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह बुलडोजर राज्य नहीं है, यह

पश्चिम बंगाल है। कृपया राज्यवासियों को बचाइए।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता धीराज त्रिवेदी ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने अदालत में कहा कि याचिका में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि किस स्थान पर क्या घटना हुई। उनका कहना था कि राज्य पुलिस सतर्क और सक्रिय है तथा जिन 2000 से अधिक शिकायतों का उल्लेख किया जा रहा है, उनके समर्थन में कोई ठोस विवरण नहीं दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से यह भी दलील दी गई कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए पहले ही पांच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ गठित की जा चुकी थी। ऐसे में अदालत को पहले यह देखना चाहिए कि वर्तमान घटनाएं वास्तव में चुनाव बाद हिंसा की श्रेणी में आती हैं या नहीं, उसके बाद ही किसी अंतरिम आदेश पर विचार होना चाहिए।

यह जनहित याचिका तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के पुत्र और अधिवक्ता शीर्षान्य बनर्जी ने दायर की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की पीठ में हुई। उल्लेखनीय है कि, इससे पहले ममता बनर्जी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय भी पहुंची थीं, जहां उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं। 294 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर पुनर्मतदान की घोषणा के कारण 293 सीटों के परिणाम घोषित किए गए। कांग्रेस को दो, माकपा को एक, आईएसएफ को एक और एजेयूपी को दो सीटें मिली हैं।

सार समाचार

हड़ताल के बीच 10 सफाई कर्मचारियों पर मामला दर्ज

सोनीपत,एजेंसी। हरियाणा के सोनीपत में नगर निगम कर्मचारियों की जारी हड़ताल के बीच 10 सफाई कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों पर सफाई सेवाओं में बाधा डालने, सरकारी कार्यों में रुकावट पैदा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाये हैं। संयुक्त आयुक्त मीतू धनखर और स्वच्छता निरीक्षक सुंदर की शिकायत पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने 10 कर्मचारियों को नामजद करते हुए कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। प्रशासन के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों को रोक दिया और नगर निगम कार्यालय के बाहर कचरा फेंका, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई।

हरियाणा के किसान देशभर में सीखेंगे आधुनिक खेती की तकनीकें

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए नयी पहल शुरू की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिले से प्रगतिशील किसानों को 'एक्सपोजर विजिट' पर भेजा जाएगा, ताकि वे देश के विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही उन्नत कृषि पद्धतियों का अध्ययन कर सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती, नयी तकनीकों और बाजार व्यवस्था की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य के हजारों किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सुधारों और सफल मॉडलों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण में किसानों को अनुभव आधारित दौरों पर भेजने की घोषणा की थी।

मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना का हुआ आधुनिकीकरण: भजनलाल

नागौर, एजेंसी।

- कहा, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महापुरूषों का प्रदेशभर में पेनोरमा बनवाया जा रहा है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुए भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रक्षा क्षेत्र में नई गति मिली है।

शर्मा आज नागौर जिले के मेड़ता में श्री राव दूदाजी के मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त कर सबक सिखाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि श्री राव दूदाजी ने प्रदेश और समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने आह्वान किया कि इन वीरों से प्रेरणा लेकर राजस्थान की इस महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्मिता और मातृभूमि की रक्षा के लिए राजस्थान के वीर किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते हैं। राव दूदाजी ने वीरता-स्वाभिमान की ऐसी परम्परा स्थापित की है, जिसने पूरे राजस्थान को विश्वभर में गौरवान्वित किया है। साथ ही उन्हीं के वंश में मीरा बाई जैसी कृष्ण भक्त भी हुईं। मीरा की वाणी कालजयी हैं। सदियों बाद भी उनकी वाणी भक्ति और मानवता का सन्देश दे रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महापुरूषों का प्रदेशभर में पेनोरमा बनवाया जा रहा है। श्री महावीर जी पेनोरमा-करौली, श्री विद्यासागर महाराजा-अजमेर, भक्त शिरोमणि करमा बाई-डीडवाना, श्री जसनाथ-बीकानेर, श्री खेमा बाबा-बालोतरा, श्री भामाशाह-चित्तौड़गढ़, श्री राव चंद्रसेन-जोधपुर का निर्माण कराया जा रहा है वहीं बांदीकुई में संत दुर्बलनाथ का पेनोरमा, सिवाना में वीर दुर्गादास तथा सलूंबर में हाड़ी रानी और अजमेर में महर्षि दयानन्द सरस्वती पेनोरमा का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही, खरनाल-नागौर में वीर तेजाजी पेनोरमा का विकास कार्य भी कराया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि, बिजली, पानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ माही, देवास, सोम-कमला-अम्बा आदि परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही 24 जिलों में किसानों को अब दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए युवा नीति लेकर आई है तथा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से जयपुर में 23 से 25 मई, 2026 को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में ग्राम विकास रथों के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने किसानों को कृषि प्रसंस्करण और नवीनतम तकनीकों की जानकारी तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए इस आयोजन में भाग लेने का आह्वान किया।

पंजाब की बेटियां शिक्षा पुनर्जागरण की कर रही हैं अगुवाई: मान

चंडीगढ़, एजेंसी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि राज्य की बेटियां शिक्षा के पुनरुत्थान में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने एक बार फिर मेरिट सूची और पास प्रतिशत में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने 500 में से 500 अंक हासिल कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तीन छात्राओं सुपनीत कौर, सुहानी चौहान और दिवांशी को चंडीगढ़ में सम्मानित किया। तीनों छात्राओं को 50-50 हजार रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।

मान ने कहा कि यह गर्व की बात है कि तीनों टॉपर छात्राएं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी हैं, जो दर्शाता है कि लड़कियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी छात्राएं साधारण परिवारों से आती हैं और मेहनत एवं समर्पण से सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं।

पंजाब सरकार उनके सपनों को पूरा करने में हरसंभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष लगभग 2.65 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से करीब 2.42 लाख उत्तीर्ण हुए। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.46 प्रतिशत रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.73 प्रतिशत जबकि छात्रों का 88.52 प्रतिशत रहा। उन्होंने बताया कि अमृतसर जिले ने 96 प्रतिशत परिणाम के साथ राज्य में सबसे अधिक पास प्रतिशत दर्ज किया है, जबकि पटियाला जिले के सर्वाधिक 59 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान बनाया है। सरकारी स्कूलों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 416 सरकारी स्कूलों ने 100 प्रतिशत परिणाम दर्ज किया है। मेरिट सूची में शामिल 275 विद्यार्थियों में से 122 सरकारी स्कूलों के छात्र हैं, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय ने साबित कर दिया है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने अपनी प्रतिभा, कौशल और क्षमता का लोहा मनवाया है।

व्यक्ति का चरित्र सत्ता को बनाता है महान: शेखावत

जोधपुर, एजेंसी।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कोई व्यक्तित्व सत्ता से महान नहीं बनता, अपितु व्यक्ति का चरित्र सत्ता को महान बनाता है।

शेखावत गुरुवार को पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत बाबोसा की आदम कद प्रतिमा अनावरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री भैरों सिंह शेखावत ने अपनी निरंतर साधना और लोगों को जोड़ने के अद्भुद कौशल से इसे सिद्ध कर दिखाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोग उन्हें अपना अभिभावक स्वरूप मानते थे।

उन्होंने कहा कि भैरों सिंह शेखावत की राजनीति में कटुता नहीं थी, उनकी राजनीति संवाद की थी। उनकी राजनीति में विरोध अवश्य था लेकिन वैमनस्य कहीं भी नहीं था। वह कुशल प्रशासक के साथ में एक कठोर प्रशासक भी थे। उन्होंने आज के राजस्थान में सुशासन की नींव रखी और उस समय जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया। उन्होंने कहा, बिना सोशल मीडिया के भी अगर, राजस्थान के हर गांव और घर की खबर किसी नेता के पास होती थी, तो वह भैरों सिंह शेखावत के पास होती थी, क्योंकि वह लोगों के सुख-दुख के साझेदार थे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान की भूमि ने अनेक वीर-सूरमा, संत और महान व्यक्तित्व पैदा किए, इन सब में भैरों सिंह शेखावत का व्यक्तित्व अतुलनीय था। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर उन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर राजनीति में असाधारण मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि एक साधारण सब इंस्पेक्टर से अपना करियर शुरू कर तीन बार राजस्थान का मुख्यमंत्री और देश का उपराष्ट्रपति बनकर अपनी इस असाधारण यात्रा को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि भैरों सिंह शेखावत और उस पीढ़ी के महान लोगों ने राज्य में पार्टी को विशाल बट वृक्ष बनाया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी राज्य में आज मजबूती से टॉप मुकाम पर खड़ी है।

मुख्य सचिव ने की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा

रायपुर, एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में विभिन्न विभागों की जनोन्मुखी और महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने पांचवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अनुशंसाओं पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली और अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचना चाहिए। इसके लिए उन्होंने डेटा आधारित निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने पर जोर दिया।

बैठक में सुशासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्षमता विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। शिक्षा और बच्चों के पोषण को प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवनों की समस्या है, वहां प्राथमिक शालाओं के अतिरिक्त कक्षों में आंगनबाड़ी संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कलेक्टरों के साथ समन्वय करने को कहा। समग्र शिक्षा के तहत जिन स्कूलों में कमरों की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

अवैध रेत खनन रोकने पुलिस ने शुरू की गांधीगिरी

मुरैना,एजेंसी। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन रोकने के प्रयासों के बीच पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को जागरूक कर 'गांधीगिरी' के जरिए इस कारोबार पर अंकुश लगाने की पहल शुरू की है। सूत्रों के अनुसार चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में न्यायालय द्वारा रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद रेत माफिया अवैध खनन और परिवहन का कारोबार लगातार संचालित कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा की गई सख्ती के बावजूद माफिया नए-नए तरीके अपनाकर गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। जानकारी के अनुसार नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने चंबल नदी किनारे बसे गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को अवैध खनन नहीं करने और न किसी को करने देने की शपथ दिलाई है। इसके बाद ग्रामीण कथित रूप से अवैध कारोबार में शामिल लोगों की जानकारी पुलिस और प्रशासन को देने लगे हैं।

छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल देशभर के लिए प्रेरणादायी: पासवान

रायपुर, एजेंसी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले के सेरीखेड़ी स्थित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत संचालित इस केंद्र में उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और आजीविका गतिविधियों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित अजा (AJA) परियोजना और बेहतर बाजार लिंकेज की प्रशंसा करते हुए इसे देशभर के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया।

पासवान ने एकीकृत बकरी पालन मॉडल अजा के क्रियान्वयन को बारीकी से देखा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ा रही है, बल्कि वैज्ञानिक पशुपालन को भी नई दिशा दे रही है। आधुनिक शेड, नियमित टीकाकरण, पशु बीमा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और जैविक खाद निर्माण जैसी व्यवस्थाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के लिए बाजार की सुलभ उपलब्धता को अन्य राज्यों के लिए भी सीखने योग्य बताया।

उन्होंने निरीक्षण के दौरान नवा रायपुर में संचालित ई-ऑटो सेवा "प्रोजेक्ट पिंक दीदी" की सराहना की। उन्होंने हितग्राही महिलाओं से संवाद कर उनके अनुभव जाने और कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। एकीकृत बकरी पालन परियोजना, कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों, आजीविका सेवा केंद्र, के अलावा उन्होंने बिजनेस दीदी, मशरूम उत्पादन और कृषि आधारित अन्य गतिविधियों का भी अवलोकन किया। पासवान ने कृषक उत्पादक समूह की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महिलाओं से आत्मीय चर्चा की। इस दौरान दीदियों ने साझा किया कि कैसे वे घर की चारदीवारी से निकलकर आज एक संगठित व्यवसाय का नेतृत्व कर रही हैं। मंत्री ने महुआ कुकीज का स्वाद लिया और समूह की दीदियों के कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र को संगठित कर लाभ अर्जित करना ही वास्तविक सशक्तिकरण है।

चौधरी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और खर्च को लेकर उठाए सवाल

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उन पर हुए कथित खर्च को लेकर गंभीर सवाल खड़े उठाए हैं। ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए आज श्री राहुल गांधी के 22 वर्षों के राजनीतिक करियर के दौरान की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा साझा किया है। इससे पहले नई दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की निजी विदेश यात्राओं और उनके वित्तीय स्रोतों को लेकर सवाल उठाए। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने अब तक 54 विदेश यात्राएं की हैं, जिनमें इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देश शामिल हैं।

उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने हज़रतबल अस्पताल के उन्नयन परियोजना को मंज़ूरी दी

श्रीनगर, एजेंसी।

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में श्रीनगर मास्टर प्लान-2035 के तहत बफर जोन प्रतिबंधों में ढील देकर उप-जिला अस्पताल हजरत बल के उन्नयन (अपग्रेडेशन) को मंजूरी दे दी गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि इस फैसले का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मरीजों की देखभाल में सुधार करना है।

मंत्रिपरिषद की छठी बैठक के दौरान लिए गए एक अन्य बड़े फैसले में, सरकार ने श्रीनगर के अछन में 361 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 800 टीपीडी (टन प्रति दिन) क्षमता वाली एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य शहर में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना और नगर निगम के ठोस कचरे का पर्यावरण के अनुकूल निष्पादन सुनिश्चित करना है।

प्रवक्ता ने बताया कि उप-जिला अस्पताल हजरतबल की परियोजना बफर जोन प्रावधानों के कारण कई वर्षों से रुकी हुई थी, जिससे जनता को काफी असुविधा हो रही थी। लोगों की कठिनाइयों और क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रतिबंधों में ढील दी, जिससे अस्पताल के लंबे समय से लंबित काम का रास्ता साफ हो गया।

इस मंजूरी के बाद अस्पताल में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और ब्लड बैंक सेवाओं, ऑपरेशन थिएटरों तथा विभिन्न बीमारियों के लिए विशिष्ट उपचार सुविधाओं सहित बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए अन्य अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने बताया कि अछन में प्रस्तावित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्देश्य आधुनिक और कुशल प्रणालियों के माध्यम से कचरे के संग्रह, पृथक्करण, उपचार और निपटान की क्षमता को बढ़ाना है। इस परियोजना से श्रीनगर शहर में स्वच्छता मानकों में सुधार होने, पर्यावरण प्रदूषण कम होने और स्वच्छ एवं स्वस्थ शहरी परिवेश के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है। यह सुविधा तेजी से हो रहे शहरी विस्तार और जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए शहर की भविष्य की कचरा प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी।

दूषित खाद्य सामग्री के सेवन से 48 बच्चे बीमार

श्रीगंगानगर,एजेंसी। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के जैतसर कस्बे में वाटर पार्क में पिकनिक मनाने गये एक निजी स्कूल के बच्चे दूषित खाद्य सामग्री के सेवन से बीमार हो गये। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैतसर स्थित जीनियस कान्वेंट स्कूल की कक्षा एक से आठवीं तक के करीब 48 बच्चे आज श्रीगंगानगर से सात किमी दूर नेतेवाला में एक वाटर पार्क घूमने गये थे।

वहां नहाने-खेलने का मजा लेते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गयी। उल्टी, पेट दर्द और अन्य लक्षण दिखने लगे। स्कूल स्टाफ ने तुरंत सभी बच्चों को श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती कर लिया गया।

इसका पता चलने पर जिला अस्पताल पहुंचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अजय सिंगला ने स्पष्ट किया कि बच्चों ने वाटर पार्क में कुछ नहीं खाया-पीया था।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार ऐसे करीब 250 मामले हैं, जिनमें कस्टोडियल डेथ होने के बावजूद अब तक न्यायिक जांच नहीं हुई

हिरासत में मौत और दुष्कर्म मामलों में न्यायिक जांच होगी अनिवार्य: हाईकोर्ट

रांची, एजेंसी।

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पुलिस कस्टडी और जेल में होने वाली मौतों (कस्टोडियल डेथ) एवं दुष्कर्म की घटनाओं से संबंधित जनहित याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि अब राज्य में पुलिस या जेल कस्टडी में होने वाली किसी भी मौत या दुष्कर्म के मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी (न्यायिक जांच) कराना पूरी तरह अनिवार्य होगा। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 196(2) और पूर्ववर्ती कानून सीआरपीसी की धारा 176(1-ए) के तहत इस न्यायिक जांच को अनिवार्य घोषित किया है।

गौरतलब है कि पूर्व में झारखंड सरकार पुलिस या जेल हिरासत में होने वाली मौतों और दुष्कर्म के मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कार्यपालक दंडाधिकारी) से कराती थी और राज्य में न्यायिक जांच को अनिवार्य नहीं माना जा रहा था। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। इसके साथ ही खंडपीठ ने झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) को निर्देश दिया है कि वह हिरासत में मौत या दुष्कर्म के मामलों में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नई दिल्ली की गाइडलाइंस के अनुरूप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करे, ताकि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष और सही ढंग से जांच सुनिश्चित की जा सके।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार ऐसे करीब 250 मामले हैं, जिनमें कस्टोडियल डेथ होने के बावजूद अब तक न्यायिक जांच नहीं कराई गई है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने संबंधित जिलों के जिला जजों (डिस्ट्रिक्ट जजों) को निर्देश दिया है कि वे इन मामलों में न्यायिक जांच न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अपनी विस्तृत रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट को सौंपें। इस मामले की पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था।

शपथ पत्र में सरकार ने स्वीकार किया था कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच झारखंड में पुलिस और जेल कस्टडी में करीब 500 मौतें हुई हैं। इनमें से लगभग आधे मामलों में ज्यूडिशियल इंक्वायरी नहीं कराई गई थी। इसके बाद अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले में प्रार्थी मोहम्मद मुमताज अंसारी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता शादाब अंसारी ने लिखित बहस के साथ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अदालत ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने ईंधन बचाने और खर्च घटाने के सख्त कदम उठाए

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और देसी संसाधनों को बढ़ावा देने की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए सभी विभागों में ऊर्जा बचाने और खर्च घटाने के कई सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।इन नए निर्देशों की जानकारी देने वाला एक सरकारी परिपत्र हाल ही में जारी किया गया है।

हाल ही में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। सरकारी दौरों और शहर से बाहर की यात्राओं के दौरान, काफिले को तय सीमा से ज़्यादा गाड़ियों की अनुमति नहीं होगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक सीधे तौर पर ज़िम्मेदार होंगे।

परिपत्र के अनुसार राज्य के खजाने पर बोझ कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के मकसद से उठाए गए एक और बड़े कदम के तहत, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सभी प्रस्तावित विदेश दौरे रद्द कर दिए गए हैं। विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे विदेश यात्राओं की कोई नई योजना न बनाएं। मंत्रियों को सलाह दी गई है कि वे बहुत ज़रूरी सरकारी काम को छोड़कर विशेष विमानों या हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करने से बचें और इसके बजाय नियमित वाणिज्यिक उड़ानों का इस्तेमाल करें।

परिपत्र में सभी सरकारी विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी संभव हो, बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और चर्चाएँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही की जाएँ। अगले छह महीनों तक किसी भी नए सलाहकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

दफ्तरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि काम के घंटों के बाद लाइटें, पंखे, कंप्यूटर और एयर-कंडीशनर बंद कर दिए जाएँ।

लखनऊ से भिड़ंत में चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें प्लेऑफ़ पर

अपने बाकी मैच सम्मान बचाने और दूसरी टीमों के सपनों को तोड़ने के लिए खेलेगी लखनऊ

लखनऊ, एजेंसी। सीज़न की शुरुआत में हार का सामना करने के बाद अचानक प्लेऑफ़ में जगह बनाने के सबसे मज़बूत दावेदारों में से एक बनने वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने कैंपेन को काफ़ी बदल दिया है और अब शुक्रवार को 59वें मैच में बाहर हो चुकी लेकिन खतरनाक दिखने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स 20 लीग मैच6 से एक अनचाही चुनौती का सामना कर रही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में, दांव आधिकारिक तौर पर सिर्फ़ एक तरफ़ हो सकते हैं, लेकिन दोनों टीमों से जुड़ी इमोशनल बातें इस मुकाबले में और दिलचस्पी जगाती हैं जो प्लेऑफ़ की दौड़ पर काफ़ी असर डाल सकती हैं।

चेन्नई के लिए, मिशन सीधा है: जीत का सिलसिला जारी रखना और टॉप-4 में अपनी पकड़ मज़बूत करना। लखनऊ, जो एक उतार-चढ़ाव भरे कैंपेन के बाद पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुका है, के लिए बाकी मैच इज़्ज़त बचाने और दूसरों के सपनों को तोड़ने का आखिरी मौका है। इस सीज़न में सीएसके से ज़्यादा तेज़ी से किस्मत बदलने वाली कुछ ही टीमों ने देखा है। चेन्नई फ्रेंचाइजी ने अपने कैंपेन की शुरुआत लगातार तीन हार के साथ की, जिससे टीम के बैलेंस को लेकर आलोचना हुई और अनुभवी खिलाड़ी एमएस धोनी के अलावा बाकी खिलाड़ियों की चिंता भी हुई, जो इस सीजन में नहीं खेले हैं।

लेकिन हार मानने के बजाय, सीएसके ने डिसिप्लिन्ड बॉलिंग, निडर बैटिंग और युवा मैच-विनर खिलाड़ियों के आने से खुद को लगातार फिर से बनाया। कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की लीडरशिप में, चेन्नई ने अब अपने पिछले आठ मैचों में से छह जीते हैं और लगातार तीन जीत के साथ लखनऊ पहुंची है। यह वापसी संजू सैमसन के लगातार अच्छे प्रदर्शन से हुई है, जिन्होंने 11 पारियों में 169 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 430 रन बनाए हैं।

धीमी शुरुआत के बाद, सैमसन ने दो सेंचुरी के साथ लय वापस पाई और तब से सीएसके की बैटिंग लाइन-अप का सेंटरपीस बन गए हैं। एक और बड़ा बूस्ट विकेटकीपर-बल्लेबाज उर्विल पटेल से मिला है, जिन्होंने सीजन का पहला हाफ बेंच पर बिताया, लेकिन तुरंत असर दिखाया। एलएसजी के खिलाफ़ रिवर्स मैच में सिर्फ़ 23 गेंदों पर उनकी ज़बरदस्त 65 रन की पारी ने सीएसके के वापसी के दौरान अपनाए गए अटैकिंग अप्रोच को दिखाया।

बॉलिंग डिपार्टमेंट ने भी प्रेशर में अच्छा किया है। हरियाणा के पेसर अंशुल कंबोज 19 विकेट लेकर टूर्नामेंट की खोजों में से एक बनकर उभरे हैं, जबकि इंग्लिश ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने 14 विकेट लेकर पेस और कंट्रोल जोड़ा है। अफ़गान स्पिनर नूर अहमद और कैरेबियाई लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील होसेन ने बीच के ओवरों में और मज़बूती दी है। इस बीच, लखनऊ का सीज़न उल्टी दिशा में गया है।

पंजाब लगातार पांचवां मैच हारी: मुंबई 6 विकेट से जीती

आखिरी ओवर में 15 रन बनाए, तिलक ने नाबाद 75 रन की पारी खेली

धर्मशाला। मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, जिसे टीम ने हासिल कर लिया। जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने नाबाद 75 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। दूसरी ओर पंजाब की यह लगातार पांचवीं हार रही।

गुरुवार को धर्मशाला के स्टेडियम में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 19.5 ओवर 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया।

तिलक-जैक्स के बीच अर्धशतकीय साझेदारी मुंबई के लिए तिलक ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 75 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनके अलावा रायन रिकल्टन ने 48 रन और विल जैक्स ने अंत में 10 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाकर मैच फिनिश किया।

पजांब के लिए अजमतुल्लाह ओमरजई ने 2 विकेट लिए, जबकि युजवेंद्र चहल और मार्को यानसन को 1-1 सफलता मिली।

पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए, जबकि अजमतुल्लाह ओमरजई ने 17 गेंदों में 38 रन की विस्फोटक पारी खेली। आखिर में जेवियर बार्टलेट ने 7 गेंदों में नाबाद 18 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचाया। प्रभसिमरन और प्रियांश के बीच पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी हुई। वहीं, प्रभसिमरन ने दूसरे विकेट के लिए कोनोली के साथ 57 रन जोड़े।

मुंबई के लिए शार्दूल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट लिए।

सीएसके के जेमी ओवर्टन आईपीएल से बाहर

चेन्नई,एजेंसी। आईपीएल 2026 में प्लेऑफ़ में पहुंचने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को एक और बड़ा झटका लगा है क्योंकि ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन जांघ की चोट की जांच के लिए वापस इंग्लैंड लौट गए हैं। चेन्नई ने ओवर्टन की जगह डियान फॉरेस्टर को टीम में शामिल किया है। डियान फॉरेस्टर ओवर्टन की जगह 75 लाख रुपये में सीएसके में शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर फॉरेस्टर ने मार्च 2026 में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था और उन्होंने पाँच इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 83 रन बनाए हैं। सीएसके ने बुधवार रात को सोशल मीडिया पर कहा, जेमी ओवर्टन को दाईं जांघ में चोट लगी है और चोट से संबंधित आगे की जांच और प्रबंधन के लिए वह स्वदेश लौटेंगे।

इस सीजन में इस समय तक ओवर्टन 17.78 की औसत और 8.89 की इकॉनमी के साथ 14 विकेट लेकर सीएसके के लिए दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। सीएसके के पिछले मुक़ाबले में वह प्लेयर ऑफ़ द मैच रहे थे। 11 मई को एलएसजी के ख़िलाफ़ चेपॉक में सीएसके की पांच विकेट से जीत में उन्होंने तीन विकेट हासिल किए थे। बुधवार को ही सीएसके ने चोट के चलते सीज़न से बाहर हुए रामकृष्ण घोष की जगह कर्नाटक के ऑलराउंडर मक्नील नोरोन्हा को अपने दल में शामिल किया था। इससे पहले तक इस सीज़न में सीएसके के कुल चार खिलाड़ी पूरे सीज़न से बाहर हो चुके हैं।

ऑरेंज कैप टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचे विराट कोहली

रायपुर, एजेंसी। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ नाबाद 105 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबील) केवल जीत दिलाई। इसी के साथ वह ऑरेंज कैप तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गये है। वहीं गेंदबाजी सूची में भुवनेश्वर कुमार 22 विकेटों के साथ शीर्ष पर पहुंच गये है। विराट कोहली ने रायपुर में केकेआर के खिलाफ आरसीबी के लिए 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आईपीएल करियर का नौवां शतक लगाया।

इस पारी की बदौलत वह इस सीजन सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। केकेआर के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी के बाद कोहली के आईपीएल की 12 पारियों में 165.75 के स्ट्राइक रेट से 484 रन हो गये हैं। उनसे आगे केवल बी साई सुदर्शन (501 रन) और हाइनरिक क्लासन (508 रन) हैं। चौथे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा 481 रन हैं। दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल 477 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल के नाम 467 रन हैं।

पर्पल कैप तालिका में भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 2016 और 2017 में पर्पल कैप जीती थी, अब कगिसो रबाडा से आगे निकल गए हैं। केकेआर के खिलाफ एक विकेट लेकर भुवनेश्वर के अब 22 विकेट हो गए हैं, जबकि रबाडा के नाम 21 विकेट हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कम्बोज 19 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव, गुजरात टाइटंस के राशिद ख़ान, केकेआर के कार्तिक त्यागी और सनराइजर्स हैदराबाद के इशान मलिंगा के नाम 16-16 विकेट हैं।

सिंधु, सात्विक-चिराग, लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में

पटुमवान, एजेंसी। तीन सीडेड भारतीय एंट्री, जिनमें सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी (1), पीवी सिंधु (6), और लक्ष्य सेन (7) शामिल हैं, गुरुवार को थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सात्विक-चिराग ने अपने मलेशियाई अपोनेंट्स गुंटिंग ब्रायन जेरेमी और हाइकल मुहम्मद को 21-12, 21-19 से हराया, सिंधु ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज़ के खिलाफ 21-13, 21-15 से जीत हासिल की, जबकि लक्ष्य ने चीन के झू झुआन चेन पर 21-12, 21-13 से शानदार जीत दर्ज कर अंतिम आठ में अपनी जगह पक्की कर ली।

वर्ल्ड टूर फ़ाइनल्स 2025 में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाली सात्विक और चिराग की जोड़ी ने अपने मलेशियाई विरोधियों को 44 मिनट में सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाई, जहाँ उनका मुकाबला जापान की छठी वरीयता प्राप्त ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी से होगा। सिंधु ने शुल्ज़ पर एक जैसे गेम में दबदबा बनाया और 28 मिनट में 21-13, 21-15 से जीत हासिल की।

भारतीय स्टार ने दोनों गेम में लगातार सात पॉइंट बनाए, पहले गेम में 9-6 से 15-6 और दूसरे गेम में 9-7 से 15-7 तक, और आगे बढ़ीं। क्वार्टर फ़ाइनल में सिंधु का सामना जापान की वर्ल्ड नंबर 3 अकाने यामागुची से होगा, जहाँ भारतीय खिलाड़ी के पास 15-12 की बढ़त है।

पुरुषों के सिंगल्स में, सेन ने चेन पर सीधे गेम में आसान जीत दर्ज की। लक्ष्य का अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल में दूसरी सीड कुनलावुत विटिडसार्न से होगा, जिसमें थाई शटलर ने भारतीय खिलाड़ी पर 7-4 की बढ़त बना रखी है।

बिजनेस

भारत में तेजी से बढ़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी वार्षिक बिक्री में वित्त वर्ष 35 तक बढ़कर 35-40 प्रतिशत हो सकती है, जो कि फिलहाल करीब 7 प्रतिशत के आसपास है। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी बसों की हिस्सेदारी बढ़कर 85 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। यह जानकारी गुरुवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

सोने की चमक बढ़ी, चांदी में आई 0.75 प्रतिशत की गिरावट

मुंबई,एजेंसी। सोने और चांदी में गुरुवार के शुरुआती सत्र में मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। एक तरफ सोने में तेजी बनी हुई थी। वहीं, चांदी लाल निशान में थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 10:36 पर सोने का 5 जुलाई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 396 रुपए या 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,62,638 रुपए पर था।

केंद्र ने देश को समर्पित की सीईएल की सोलर मॉड्यूल निर्माण लाइन

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन देश को समर्पित कर दी। भारत इस समय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और समुद्र-आधारित ऊर्जा प्रणालियों सहित कई गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षेत्रों में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में रिन्यूएबल और स्वच्छ ऊर्जा की बड़ी भूमिका रहने वाली है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत को नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का राष्ट्रीय लक्ष्य दिया है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हर रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत की अपनी उपयोगिता और महत्व है। भारत स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और सतत विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। डॉ. सिंह ने 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन के शुरू होने को भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह सुविधा देश में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है।

सीईएल के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत का पहला सोलर सेल 1977 में सीईएल ने बनाया था। इसके अलावा देश का पहला सोलर प्लांट भी 1979 में इसी संगठन ने स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि सीईएल का सफर काफी प्रेरणादायक रहा है। एक समय यह संस्था विनिवेश की कगार पर थी, लेकिन अब यह मुनाफा कमाने वाली मिनी रत्न कंपनी बन चुकी है।

मंत्री ने कहा कि यह बदलाव मजबूत नेतृत्व, सरकारी नीतियों के समर्थन, बेहतर संचालन और संगठन से जुड़े वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए 24 अप्रैल 2025 को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया गया था। एक महीने के भीतर सफल बोलीदाता का चयन कर लिया गया और एक साल से भी कम समय में यह निर्माण सुविधा चालू हो गई।

सीईएल अब भविष्य से जुड़े कई नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही है, जिनमें वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, हाइब्रिड रिन्यूएबल सिस्टम, डेटा सेंटर, एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और छोटे हथियार प्रणालियां शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि यह भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और रणनीतिक तैयारी को दर्शाता है।

भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ हरे निशान में बंद

मुंबई, एजेंसी। वैश्विक बाजार से मिले मजबूत संकेतों के चलते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी दिन हरियाली देखने को मिली और बाजार हरे निशान में बंद हुआ। बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 789.74 अंक या 1.06 प्रतिशत उछलकर 75,398.72 पर था, जबकि निफ्टी 50 277 अंक या 1.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,689.60 पर पहुंच गया दिन के दौरान 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी50 में जोरदार उछाल देखने को मिला और इनमें 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। निफ्टी50 ने 23,530.25 पर खुलकर 23,777.20 का इंट्रा-डे हाई बनाया, तो वहीं सेंसेक्स 74,947.12 पर खुलकर 75,681.88 का दिन का उच्चतम स्तर छुआ।

व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप में 1.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेक्टरवार देखें तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी मेटल में 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखी गई। इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा करीब 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। निफ्टी 50 पैक में कुल 38 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। इसमें अदाणी इंटरप्राइजेज (8.8 प्रतिशत की तेजी), सिप्ला (8.09 प्रतिशत की तेजी), भारती एयरटेल (5.2 प्रतिशत की बढ़त), इटरनल, हिंडाल्को, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स और मैक्स हेल्थ के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जबकि इसके विपरीत इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोल इंडिया और टीसीएस के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

निवेशकों ने एक ही सत्र में 4.3 लाख करोड़ रुपए कमाए क्योंकि बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के 458.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 462.9 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रुपए के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने और ब्रेंट क्रूड तेल के 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार करने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। इस बीच, निवेशकों की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के नतीजों पर है।

महंगे कच्चे तेल का असर! थोक महंगाई दर अप्रैल में 8.3 प्रतिशत रही

नई दिल्ली, एजेंसी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर या थोक महंगाई दर अप्रैल में सालाना आधार पर 8.30 प्रतिशत (प्रोविजनल) रही है। इससे पहले मार्च में यह 3.88 प्रतिशत थी। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गुरुवार को दी गई। सरकार ने आधिकारिक बयान में कहा कि अप्रैल में महंगाई के सकारात्मक रहने की वजह खनिज तेल, कच्चे तेल और नेचुरल गैस, बेसिक मेटल, अन्य मैन्युफैक्चरिंग और गैर-खाद्य उत्पादों की कीमतों में इजाफा होना है।

आंकड़ों के मुताबिक, प्राइमरी आर्टिकल्स में थोक महंगाई दर सालाना आधार पर 9.17 प्रतिशत रही। फ्यूल एंड पावर में महंगाई दर सालाना आधार पर 24.71 प्रतिशत और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में महंगाई दर 4.62 प्रतिशत रही। हालांकि, खाद्य उत्पादों में महंगाई में नरमी बनी हुई है और अप्रैल में यह सालाना आधार पर 2.31 प्रतिशत रही है।

आंकड़ों के मुताबिक, क्रूड पेट्रोलियम की कीमत में थोक महंगाई दर में सालाना आधार पर 88.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी में थोक महंगाई दर अप्रैल में सालाना आधार पर 10.92 प्रतिशत रही है।

इससे पहले, सरकार ने खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए थे। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल में सालाना आधार पर 3.48 प्रतिशत रही है, जो कि मार्च में 3.40 प्रतिशत थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल में ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा महंगाई दर 3.74 प्रतिशत रही है। वहीं, शहरी क्षेत्र में यह 3.16 प्रतिशत थी। अप्रैल में खाद्य मंहगाई दर 4.20 प्रतिशत रही है, जो कि मार्च में 3.87 प्रतिशत थी। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर 4.26 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 4.10 प्रतिशत रही है।

सरकार ने बताया कि तेलंगाना (5.81 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (4.20 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.18 प्रतिशत), कर्नाटक (4.00 प्रतिशत) और राजस्थान (3.77 प्रतिशत) के खुदरा महंगाई में अप्रैल में शीर्ष पर थे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2026-27 के लिए देश की खुदरा महंगाई दर 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसका कारण रबी की अच्छी फसल से निकट भविष्य में खाद्य आपूर्ति की संभावनाएं बेहतर रहना है।

यूरोपीय संघ ने संशोधित मसौदा सूची में भारत को किया शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यूरोपीय संघ ने अपनी संशोधित मसौदा सूची में भारत को शामिल किया है, जिससे भारत अब यूरोपीय संघ के बाजार में जलीय कृषि उत्पादों का निर्यात जारी रख सकेगा। भारत को प्रस्तावित रूप से शामिल करना देश के समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम है और यह भारत की नियामक प्रणालियों, निगरानी तंत्रों और खाद्य सुरक्षा मानकों में यूरोपीय संघ के विश्वास को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि यूरोपीय आयोग द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए जाने के बाद, संशोधित विनियमन से सितंबर 2026 के बाद भी भारतीय मत्स्य उत्पादों का यूरोपीय संघ के बाजार में निर्बाध निर्यात सुनिश्चित होने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्यों में से एक है। वर्ष 2025-26 में यह भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा, जिसमें कुल निर्यात मूल्य 1.593 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया और यूरोपीय संघ का इसमें योगदान 18.94 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2024-25 की तुलना में यूरोपीय संघ को निर्यात में मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसमें निर्यात मूल्य में 41.45 प्रतिशत और निर्यात मात्रा में 38.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसमें फार्म में पाली गई झींगा मछलियों का निर्यात की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी। यूरोपीय संघ के इस कदम का उद्देश्य 4 अक्टूबर 2024 को जारी कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) में हुई चूक से उत्पन्न चिंताओं को हल करना है।

पहले के विनियमन में भारत उन तृतीय देशों की सूची में शामिल नहीं था, जिन्हें सितंबर 2026 से मानव उपभोग के लिए पशु मूल के उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। यूरोपीय आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि इस संशोधित सूची में केवल उन्हीं देशों को शामिल किया गया है जिन्होंने खाद्य उत्पादन में उपयोग होने वाले जानवरों पर रोगाणुरोधी उपयोग का यूरोपीय प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू किया है। इन देशों ने यूरोपीय संघ के नियमों के तहत आवश्यक गारंटी और भरोसेमंद आश्वासन भी प्रदान किए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इस घटनाक्रम को वाणिज्य विभाग, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) जैसे संगठनों द्वारा नियामक अनुपालन को सुदृढ़ करने और जिम्मेदार मत्स्यपालन नियमों को बढ़ावा देने के लिए किए गए लगातार प्रयासों की मान्यता के रूप में भी देखा जा सकता है।

सिर्फ रोमांटिक फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहतीं लिंडसे लोहान

बोलीं- 'अब अलग किरदार निभाने का समय है'

लॉस एंजिल्स। हॉलीवुड अभिनेत्री लिंडसे लोहान एक बार फिर चर्चा में हैं। फिल्म 'द पेरेंट ट्रैप' से दुनियाभर में पहचान बनाने वाली लिंडसे अब अपने करियर में नया मोड़ लाना चाहती हैं। लंबे समय तक रोमांटिक और कॉमेडी वाले किरदार निभाने के बाद वह अब गंभीर और अलग तरह की भूमिकाओं में खुद को आजमाना चाहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी आने वाली ड्रामा सीरीज 'काउंट माय लाइज' को लेकर खुलकर बात की और बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए क्यों इतना खास है।

लिंडसे लोहान ने कहा, 'यह मेरी पहली बड़ी स्क्रिप्टेड सीरीज है, जिसमें मैं पूरी तरह से मुख्य भूमिका निभा रही हूं। इससे पहले मैंने कुछ छोटे किरदार किए थे, लेकिन इस बार अनुभव बिल्कुल अलग है। इस सीरीज का किरदार मेरे पुराने सभी कामों से काफी अलग है और यही बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित कर रही है।"

लिंडसे ने कहा, "अक्सर मुझे सिर्फ रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों वाली अभिनेत्री के रूप में देखा जाता है। दर्शकों ने मुझे ज्यादातर ऐसे ही किरदारों में पसंद किया, लेकिन अब मैं खुद को एक कलाकार के तौर पर और ज्यादा साबित करना चाहती हूं। रचनात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए नए किरदार निभाना जरूरी होता है, इसलिए अब अलग तरह की कहानियों और भूमिकाओं की तलाश कर रही हूं।"

इस नई सीरीज में लिंडसे के साथ किट हैरिंगटन भी नजर आएंगे, जो मशहूर सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन' से दुनियाभर में लोकप्रिय हुए थे। शो में दोनों पति-पत्नी का किरदार निभा रहे हैं। किट हैरिंगटन ने भी इस शो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, "यह एक मजेदार और ट्विस्ट्स से भरी थ्रिलर कहानी है। शो की शूटिंग पूरी हो चुकी है और यह पहला मौका है जब मैं इसके बारे में मीडिया से बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि इस शो को लोगों के सामने किस तरह पेश करें।"

लिंडसे लोहान ने बातचीत के दौरान अपने पुराने दिनों को भी याद किया। उन्होंने कहा, 'छोटी उम्र में अचानक मिली लोकप्रियता मेरे लिए आसान नहीं थी। फिल्म 'द पैरेंट ट्रैप' से मशहूर होने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उस समय मुझे अपने माता-पिता की बात मानकर न्यूयॉर्क लौट जाना चाहिए था, लेकिन मैं लॉस एंजेलिस में रहना चाहती थी।'

अभिनेत्री ने कहा, "अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि किशोर उम्र में इंसान खुद यह नहीं समझ पाता कि उसे किस तरह अपने फैसले लेने चाहिए। लोकप्रियता और ग्लैमर की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल भी होती है।"

लिंडसे लोहान ने कहा, "एक समय ऐसा आ गया था जब मैं फिल्मी दुनिया से बोर हो गई थी। मुझे ऐसे किरदार नहीं मिल रहे थे, जिन्हें मैं सच में करना चाहती थी। लगातार चर्चा में रहना और निजी जिंदगी पर नजर रखे जाना भी मुझे परेशान करने लगा था। इसी वजह से मैंने साल 2014 में दुबई जाकर रहने का फैसला लिया।"

जहां मैं पली-बढ़ी, वहां बॉडी शेमिंग करना सामान्य था : भारती सिंह

मुंबई। भारती सिंह आज के समय भारत की नामी कमीडियन में शुमार हैं। वह अक्सर अपने ही अंदाज, हाजिरजवाबी और हल्के-फुल्के मजाक का इस्तेमाल करती हैं। हाल ही में उन्होंने नेहा धूपिया-अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में बॉडी शेमिंग को लेकर अपने अनुभव शेयर किए।

भारती सिंह पंजाब के अमृतसर से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने पंजाब से मुंबई का सफर तय कर अपना नाम एक फेमस कमीडियन के तौर पर स्थापित किया है। भारती सिंह ने नेहा धूपिया के साथ बातचीत में बताया कि जिस माहौल में वह पली-बढ़ी हैं, वहां पर बॉडी शेमिंग सामान्य बात मानी जाती है।

कमीडियन ने बचपन की यादें शेयर करते हुए बताया कि उनके गृहनगर में लोग किसी भी व्यक्ति को उसकी कमी के अनुसार बुला लेते हैं। उन्होंने कहा, 'अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है, तो उसे लोग मोटा कहकर पुकारते थे और अगर कोई सांवले रंग का होता था, तो उसे काला कहकर पुकारते थे। बिना इस बात की परवाह किए कि ऐसे शब्दों का दूसरे व्यक्ति की भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा।'

भारती सिंह ने आगे बातचीत में बताया कि अक्सर उनकी मां भी उनसे मजाक में कहती थीं, 'बस कर, कितना खाएगी, मोटी हो जाएगी।'उन्होंने बताया कि काफी समय तक उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसी बातें किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान को कितनी गहराई से चोट पहुंचा सकती है।

उन्होंने कहा, 'जब मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हुई, तो मैंने देखा कि अक्सर हंसी-मजाक के लिए लोगों के शरीर या बनावट पर मजाक बनाए जाते थे। हालांकि, फिर समय और समझदारी के साथ मैंने फैसला लिया कि दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी।'

कमीडियन भारती सिंह ने बताया कि इस एहसास ने उनके नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा, 'फिर, मैंने दूसरों के शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाने के सिवाय, खुद पर ही मजाक करना शुरू कर दिया और इस बात का खास ध्यान रखा कि मेरी कॉमेडी किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए।'

बेटे अव्यान के जन्मदिन पर भावुक हुईं दीया मिर्जा

बोलीं- 'तुम्हारे आने से जिंदगी में उम्मीद के मतलब ही बदल गए'

मुंबई। दीया मिर्जा अपनी निजी जिंदगी और परिवार को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बेटे अव्यान आजाद की तस्वीरें और खास पल फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। इस कड़ी में उन्होंने बेटे के पांचवें जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया और अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि अव्यान को अपनी जिंदगी में नई रोशनी बताया।

दीया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर बेटे अव्यान आजाद की कई तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में अव्यान के शुरुआती पल से लेकर अब तक की कई खूबसूरत फोटोज हैं। कुछ तस्वीरों में दीया अपने बेटे का साथ खेलती, मुस्कुराती और परिवार के साथ समय बिताती दिखाई दे रही हैं।

इन तस्वीरों के साथ दीया मिर्जा ने अपने बेटे के लिए लंबा कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा, "हमारे मिरेकल बच्चे को पांचवें जन्मदिन की शुभकामनाएं। हमारा बहादुर, तुम जन्म से ही आजाद थे और हमेशा आजाद रहो। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। खुलकर हंसो, दिल से प्यार करो और बड़े सपने देखो।"

उन्होंने आगे लिखा, "तुम हमेशा उन चीजों की रक्षा करो, जो कोमल और खूबसूरत हैं। हमेशा नई चीजों को बढ़ने और आगे बढ़ाने में मदद करो। तुम्हारे हमारे जिंदगी में आने के बाद उम्मीद का मतलब ही बदल गया। तुम जिंदगी की धूप हो, नई रोशनी हो। मैं अपने प्यार को शब्दों में बयां नहीं कर सकती।"

बता दें कि अव्यान का जन्म समय से पहले हुआ था। जन्म के बाद उन्हें करीब दो महीने एनआईसीयू में बिताने पड़े थे। दीया मिर्जा पहले भी कई बार बता चुकी हैं कि वह समय उनके लिए कितना भावुक और डर से भरा हुआ था।

दीया मिर्जा ने वैभव रेखी से साल 2021 में शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने बेटे के जन्म की खबर साझा की थी।

विदेश

बांग्लादेश में खसरे से आठ की मौत, संख्या बढ़कर 432

ढाका। बांग्लादेश में खसरे और उससे मिलते-जुलते लक्षणों से होने वाली मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में आठ और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 432 हो गई है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने स्वास्थ्य विभाग के हवाले से दी है।

लातविया की प्रधानमंत्री इविका सिलिना ने दिया इस्तीफा

रीगा। लातविया की प्रधानमंत्री इविका सिलिना ने गुरुवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की और इसे हालातों के मद्देनजर 'सही फैसला' करार दिया। स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि जब तक नए कैबिनेट मंत्रियों को मंजूरी नहीं मिल जाती, सरकार अपना काम करती रहेगी।

जिनपिंग के बयान पर ताइवान का पलटवार, चीन को इलाके में असुरक्षा का एकमात्र कारण बताया

बीजिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीन दिवसीय चीन दौरे पर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान व्यापार, तकनीक समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें ताइवान भी एक मुद्दा रहा। शी ने कहा कि अगर ताइवान के मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया, तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, ताइवान ने चीन पर इस इलाके में असुरक्षा का एकमात्र सोर्स होने का आरोप लगाया।

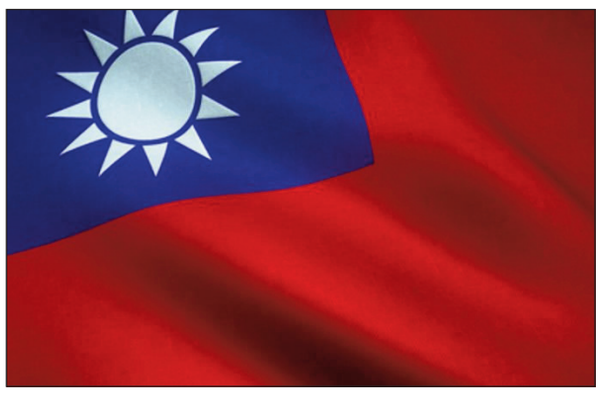

अमेरिकी मीडिया सीएनएन के अनुसार, ताइवान कैबिनेट प्रवक्ता मिशेल ली ने कहा, "ताइवान स्ट्रेट और हिंद-प्रशांत इलाके में असुरक्षा का एकमात्र सोर्स चीन का सैन्य खतरा है। क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिफेंस को लगातार बेहतर बनाना और असरदार संयुक्त निवारण सबसे जरूरी फैक्टर हैं।"

चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति शी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ताइवान चीन-अमेरिका संबंधों में सबसे जरूरी मुद्दा है और अगर इसे गलत तरीके से हैंडल किया गया तो यह बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपना दावा करती है और उसने कसम खाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक दिन वह इसे जबरदस्ती ले लेगी।

शी ने कहा, "ताइवान की आजादी और क्रॉस-स्ट्रेट शांति आग और पानी की तरह एक-दूसरे के खिलाफ हैं। ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखना चीन और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी सामान्य बात है।" बता दें, वैसे तो अमेरिका लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे ताइवान के साथ मजबूत अनौपचारिक संबंध बनाए हुए है। हालांकि, यूएस ने जानबूझकर इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बोला है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो यूएस सैन्य दखल देगा या नहीं।

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने भी इस द्विपक्षीय वार्ता के कुछ पॉइंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए, जिसमें लिखा था कि चीनी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी, 'अगर ताइवान मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया, तो दोनों देशों के बीच टकराव और यहां तक कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पूरे द्विपक्षीय संबंध खतरे में पड़ जाएंगे।'

उन्होंने जोर देकर कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता और क्रॉस स्ट्रेट पीस एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, ठीक वैसे ही जैसे आग और पानी साथ नहीं रह सकते। दरअसल, ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन का दौरा करने के बाद ट्रंप ने यूनेस्को धरोहर स्थल और चीन की जमकर सराहना की।

हालांकि, इस दौरान जब मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ताइवान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा, ट्रंप और शी जिनपिंग ने बीजिंग में अपनी बातचीत के दौरान मध्य पूर्व, यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। मंत्रालय के बयान में कहा गया, 'दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति, यूक्रेन संकट और कोरियाई प्रायद्वीप जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।'चीन ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है और ईरानी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार भी है, शायद यही वजह है कि बीजिंग तेहरान के साथ खड़ा दिख रहा है और अमेरिका से भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर मंत्रणा कर रहा है।

लेबनान हिंसा से 7.7 लाख बच्चे मानसिक तनाव का शिकार: यूनिसेफ

नई दिल्ली। यूनिसेफ ने लेबनान में जारी हिंसा के बीच लाखों बच्चों की गंभीर मानसिक स्थिति की ओर दुनिया का ध्यान दिलाया है। बताया है कि हिंसा और बड़े पैमाने पर विस्थापन से करीब 7.7 लाख बच्चे मानसिक तनाव झेल रहे हैं।

आधिकारिक साइट पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले सात दिनों में हालात और भी गंभीर बन गए हैं। 17 अप्रैल 2026 को घोषित संघर्षविराम के बावजूद करीब 59 बच्चों के मारे जाने या घायल होने की रिपोर्ट सामने आई है।लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, संघर्षविराम के बाद अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है और 93 घायल हुए हैं। वहीं 2 मार्च से अब तक कुल 200 बच्चों की जान जा चुकी है और 806 बच्चे घायल हुए हैं।

इसका मतलब है कि औसतन हर दिन लगभग 14 बच्चे या तो मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं, जो स्थिति की भयावहता को दर्शाता है। यूनिसेफ ने कहा कि ये बच्चे लगातार हिंसा, अपनों को खोने और बार-बार घर छोड़ने की मजबूरी जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इससे उनके मन पर गहरा असर पड़ रहा है, जो आने वाले कई वर्षों तक बने रह सकता है।

यूनिसेफ के मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक एडुआर्ड बेइगबेडर ने कहा, 'यदि तुरंत मदद नहीं पहुंचाई गई, तो इस संकट के मानसिक घाव बच्चों के साथ कई साल तक रह सकते हैं। इसका असर सिर्फ उनकी जिंदगी पर नहीं, बल्कि देश के भविष्य-दोनों पर पड़ेगा।'उन्होंने खेद जताते हुए कहा, 'जिन बच्चों को अब स्कूल लौटकर सामान्य जीवन जीना चाहिए, दोस्तों के साथ खेलना चाहिए और डर के माहौल से बाहर निकलना चाहिए, वे आज हिंसा में मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं।'

ईयू देशों के मिशन प्रमुखों ने की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात

नई दिल्ली। यूरोपीय संघ (ईयू) के (27 सदस्य देश) के मिशन प्रमुखों (एचओएम) ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत-यूरोपीय संघ के "मजबूत होते रणनीतिक संबंधों" और मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। कांग्रेस की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे, और ईयू प्रतिनिधिमंडल की ओर से शांति निकेतन में आयोजित लंच में शामिल हुए।

भारत में ईयू के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने एक्स पोस्ट में बताया, ₹ ईयू एचओएम की ओर से आयोजित लंच में एलओपी राहुल गांधी और कांग्रेस के विदेश मामलों की समिति अध्यक्ष सलमान खुर्शीद शामिल हुए। इस बैठक में भारत और ईयू के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार-विमर्श हुआ।

ठपिछले हफ्ते डेल्फिन ने ईयू और भारत के घनिष्ठ संबंधों की ओर ध्यान दिलाया था।

ओमान तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला 'नामंजूर': विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। भारत ने बुधवार को ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर रहा कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

एमईए के आधिकारिक बयान अनुसार, बुधवार (13 मई) को ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुआ हमला किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। हम इस बात की निंदा करते हैं कि व्यावसायिक जहाजों और आम नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय चालक दल के सुरक्षित होने की पुष्टि करते हुए ओमानी अधिकारियों का आभार जताया। लिखा कि जहाज पर सवार भारतीय क्रू सुरक्षित हैं और हम उन्हें बचाने के लिए ओमानी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं।

अंत में एक बार फिर इस कृत्य की आलोचना करते हुए कहा गया कि भारत फिर से कहता है कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाने और बेगुनाह आम क्रू सदस्यों को खतरे में डालने, या किसी और तरह से नौवहन और कॉमर्स की आजादी में रुकावट डालने से बचने की जरूरत है।

ईरान जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। 'हाजी अली' नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया।हादसे के बाद जहाज में आग लग गई, हालांकि ओमान कोस्टगार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया।कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, 13 मई की सुबह गुजरात के द्वारका निवासी और जहाज मालिक सुलतान अहमद अंसार के एमएसवी हाजी अली जहाज पानी में डूब गया। यह जहाज बेरबेरा पोर्ट से शारजाह जा रहा था। सुबह करीब 3:30 बजे ओमान के समुद्री तट के पास जहाज हादसे का शिकार हुआ।चालक दल ने बाद में बताया कि जहाज से किसी विस्फोटक जैसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी थी।